HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 अप्रैल, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 18/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

मौसम का हाल

मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आगामी दिनों में शुष्क रहेगा। अगले सप्ताह में मैदानी, कम ऊंचाई वाले और चोटियों पर शुष्क मौसम ही रहेगा । कंही–कंही बादल रहेंगे । 31 मार्च से 6 अप्रैल तक मौसम शुष्क होने के कारण तापमान में बढ़ौतरी करेगा । मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के कारण शिमला में पर्यटकों की तादात बढ़ने की संभावना है । लेकिन हिमाचल में भी गर्मी का एहसास करवाएगा ये सप्ताह ।

नर में नारायण के दर्शन केवल सेवा से ही किए जा सकते हैं : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... हिमाचल समाचार
- पृष्ठ 3 से 6...ज़िलावार ख़बरें
- पृष्ठ 7...आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श,जाने कानून व अन्य
- पृष्ठ 8...संपादकीय:
- पृष्ठ 9...अभिव्यक्ति: ये जो पब्लिक है ये.... एवं फलक पर भी हिंदुस्तानी बादशाहत
- पृष्ठ 10...प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11...राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12...अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13...समसामयिक
- पृष्ठ 14...योजनाएं
- पृष्ठ 15...कृषोन्नति योजना हरित क्रान्ति
- पृष्ठ 16...सर्विस सेवा ऐसोसियेट की भर्तियां....प्रशिक्षण एवं रोजगार

THE RIEV TIMES
OFFICIAL MEDIA PARTNER
krishi & Wellness
INDIA 2019 EXPO
Linking Agriculture, Food & Wellness
06-07-08 August 2019
Pragati Maidan, New Delhi, India

'हमारा मत ही है राष्ट्रहित'

द रीव टाइम्स आप सभी देशवासियों से अपील करता है कि चुनावों के इस महासमर में निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदार पहल करते हुए अपना मत धर्म, मज़हब, जात–पात, छोटा–बड़ा और बिना किसी भेदभाव के लोकतंत्र की मज़बूती के लिए अवश्य करें .....

आसाम में नई उड़ान–दिल से सेवा दिल से भुगतान

मिशन रीव अब आसाम में भी देगा सेवाऐं

हेम राज चौहान

हिमाचल प्रदेश में मिशन रीव संस्करण 2 की धमाकेदार शुरुआत और लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए क़दम दर क़दम आगे बढ़ते हुए नई आशाओं और जन सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। हिमाचल के बाहर भी अब देश के अन्य राज्यों में मिशन रीव अपनी जनहित सेवाओं के साथ प्रवेश कर चुका है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिशन रीव धीरे–धीरे लोगों के बीच पहुंचने की प्रक्रिया में है। इसी के तहत आसाम में मिशन रीव अब लोगों के लिए अपनी सेवाऐं देगा। गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ आईआईआरडी द्वारा आसाम के बरौनी गुवाहटी पाईपलाईन परियोजना में गैस पाईपलाईन के सर्वे और रिपोर्ट के लिए मिशन रीव मॉडल पर लोगों के बीच सर्वे किया जा रहा है जिसमें मिशन रीव के दस प्रभागों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवश्यकता आकलन को आधार बनाया गया है । इसके तहत आसाम के लोगों के प्रत्येक वर्ग में मिशन रीव द्वारा निर्धारित परियोजना के लिए आवश्यकता आकलन के उसी प्रारुप को अपनाया गया है जो हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा हेतु वर्तमान में लागु है। दरअसल गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आसाम में गैस पाईपलाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व मिशन रीव ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ संबन्धित क्षेत्रों में न केवल सर्वे करने की प्रक्रिया चल रही है बल्कि गांव–गांव में लोगों के साथ मिलकर उनकी आवश्यकता आकलन करने तथा उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर समस्याओं एवं आवश्यकताओं को जानने का प्रयास भी किया जा रहा है ।

वो क्षेत्र जहां मिशन रीव ने सर्वे किया

कमरुप मेट्रो, द्रंग, कमरुप रुरल, नलबाड़ी, बक्सा, वाटपेटा, बोंगईगांव, चिरंग और कोकराझार आदि क्षेत्र हैं जहां मिशन रीव ने घर–घर जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को जानने के लिए अभियान चलाया जा रहा है । इस कार्ययोजना के निर्माण में मिशन रीव के प्रारुप को ही आधार बनाया गया है।

दस प्रभाग जिनके तहत सामुदायिक योजना निर्माण हुआ

मिशन रीव के दस महत्वकांक्षी प्रभागों के तहत ही आसाम में इस वृहद् परियोजना के लिए कार्ययोजना निर्माण किया गया है। इसमें शामिल हैं : स्वास्थ्य प्रभाग, कृषि प्रभाग, यूटिलिटी, लाईसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसिज़, उद्यमिता और व्यवसाय विकास प्रभाग, बैंकिंग, फाईनांस और इंश्योरैंस विभाग, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रभाग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग, संपत्ति प्रबंधन प्रभाग, मीडिया,प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग।

इनमें प्रत्येक आयुवर्ग के लोगों से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं एवं समस्याओं का आकलन किया गया। यहां दीगर बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के बाहर अब अन्य राज्यों में भी मिशन रीव ने व्यवहारिक दस्तक दे दी है। हालांकि देश भर में इस नायाब पहल को वाहवाही मिल चुकी है। विभिन्न स्तरों पर मिशन रीव की चर्चा भी हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में भी मिशन रीव के प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा के बाद सराहना मिल चुकी है।

..तो देश भर में लागु करने में मदद करेगी भारत सरकार : रुपाला

मिशन रीव के अधिकारिक लाँच पर भारत सरकार के मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में मिशन रीव की सफलता के बाद इसे भारत के अन्य राज्यों में भी लागु किया जाएगा जिसमें भारत सरकार आईआईआरडी को हरसंभव सहयोग करेगी ।

क्या कहते है आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक

जन सेवा में समर्पित मिशन रीव हिमाचल के साथ–साथ अब उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अपनी सेवाऐं देने के लिए तैयार है । आसाम में जन सहयोग से इसे सफल बनाने की संभावनाओं पर विचार और अभ्यास किया जा रहा है । आसाम में लोगों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का आकलन कर मिशन रीव के दस प्रभागों के अंतर्गत घर–द्वार तक दिल से सेवाओं को प्रदान करने का लक्ष्य है । इसके लिए गोवाहाटी एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन रीव के तहत ग्रामीण परिस्थितियों एवं लोगों की समस्याओं को जानने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है । साथ ही भारत सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मिशन रीव के मूल को ही आधार बनाया गया है।

भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लाइव सैटेलाइट को मार गिराया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने अंतरिक्ष में एंटी मिसाइल से एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराते हुए अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर दर्ज करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा ,''मिशन शक्ति के तहत स्वदेशी एंटी सैटेलाइट मिसाइल 'ए..सैट' से तीन मिनट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया गया ।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष में निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है । अब तक यह क्षमता केवल अमेरिका, रूस और चीन के ही पास थी । उन्होंने वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी । उन्होंने कहा कि इससे किसी अंतरराष्ट्रीय कानून या संधि का उल्लंघन नहीं हुआ है । भारत हमेशा से अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरूद्ध रहा है और इससे : उपग्रह मार गिराने से : देश की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है । प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति एवं सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का निर्माण जरूरी है और हमारा उद्देश्य शांति का माहौल बनाना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना ।

भारतीय एंटी सैटेलाइट मिसाइल का गणित

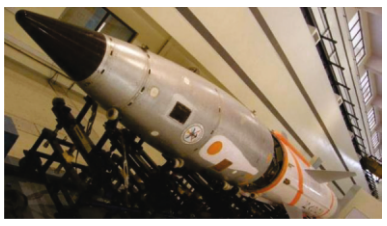

भारत के पास एंटी–सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस (पैड) सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह एक्सो–एटमॉसफियरिक (पृथ्वी के वातावरण से बाहर) और एंडो–एटमॉसफियरिक (पृथ्वी के वातावरण से अंदर) के टारगेट पर हमला करने में सक्षम हैं। यह दो स्टेज की बैलिस्टिक मिसाइल है।

पैड सिस्टम की शुरुआती क्षमता

रेंज : 2000 किमी, गति: 1470 से 6126 किमी प्रति घंटा (हालांकि, बाद में इसे अपग्रेड कर और भी ताकतवर और घातक बनाया गया है)

कैसे लॉन्च किया एंटी – सैटेलाइट मिसाइल

डीआरडीओ ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किमी की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया । यह मिसाइल भुवनेश्वर से 150 किमी दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड से छोड़ी गई ।

शिमला : चलती कार पर झपट पड़े एक साथ तीन तेंदुए, बाप–बेटा घायल

हेम राज चौहान

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कालीहट्टी में चलती कार तीन तेंदुओं ने हमला कर बाप व बेटे को घायल कर दिया। उनके शोर मचाने पर तेंदुए रात के सन्नाटे में देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। तेंदुए के हमले के बाद से इलाके लोग खौफजदा हैं। यह घटना रात के समय की है। शनिवार शाम को दोछना निवासी जिया लाल अपने बेटे के साथ कार से घर जा रहे थे। कालीहट्टी के पास एक नाले के पास से बाप–बेटा गुजरे ही थे कि अचानक तीन तेंदुए उनकी कार पर झपट पड़े। इस हमले में कारण का शीशा टूट गया। तेंदुए जियालाल पर झपट पड़े और उसे जख्मी कर दिया। जियालाल के बचाव में आया उनका बेटा भी तेंदुओं के हमले में घायल हो गया। उनके शोर मचाने पर तेंदुए भाग गए। स्थानीय पंचायत के उपप्रधान योगेश चौहान ने पुलिस व वन विभाग पूरी घटना की जानकारी दी।

उधर, उदघोष संस्था के चेयरमैन हेमराज चौहान ने बताया कि शिमला की पंचायत मायली जेजड़ व कोहबाग क्षेत्रों में तेंदुओं की दहशत है। शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ है। डीएफओ शिमला सुशील राणा ने बताया कि वन विभाग की टीम घटनास्थल पर गई थी। उस जगह तेंदुआ देखा गया है। तेंदुए को पकडने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा।

उधर, उदघोष संस्था के चेयरमैन हेमराज ने बताया कि शिमला की पंचायत मायली जेजड़ व कोहबाग क्षेत्रों में तेंदुओं की दहशत है। शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ है। डीएफओ शिमला सुशील राणा ने बताया कि वन विभाग की टीम घटनास्थल पर गई थी। उस जगह तेंदुआ देखा गया है। तेंदुए को पकडने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा।

12 मामले आए सामने

प्रदेश में अब तक तेंदुए के हमले के करीब 12 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कुछ लोग तो बहुत ज्यादा घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करना पड़ा। ये मामले वो हैं जो वन विभाग के पास रिपोर्ट किए गए हैं जबकि बहुत से मामले रिपोर्ट ही नहीं होते हैं।

आखिर क्यों रिहायशी इलाकों में दिख रहे तेंदुए

तेंदुए के आबादी क्षेत्र में दिखने के कई कारण हैं। पहला कारण जंगलों को आग के सुपुर्द करना और वहां पर भोजन का न मिलना। दूसरा यह कि रिहायशी इलाकों में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या है। यहां इस जंगली जानवर को आसानी से शिकार मिल जाता है। तेंदुए सुबह व सायं के समय खाने की तलाश में ज्यादा सक्रिय होते हैं।

नाकाम रहा वन विभाग

गांव के लोग दहशत में हैं और वन विभाग की टीम ने खाली पिंजरा नाले में लगा कर सुध ही नहीं ली है । दरअसल विभाग इन आदमखोर तेंदुओं को पकड़ना ही नहीं चाहता है । आज भी गांव में लोग दहशत में है और तेंदुऐं खुले में घूम रहे हैं ।

डाकघरों में अब मोबाइल ऐप से कर सकेंगे लेन–देन

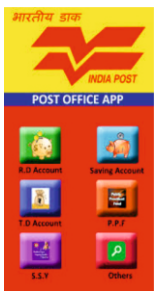

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंकों से जुड़े डाकघरों के उपभोक्ता अब मोबाइल ऐप आईपीपीबी से वित्तीय लेन–देन कर सकेंगे। अन्य मोबाइल ऐप की तर्ज पर आईपीपीबी (इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक) से भी उपभोक्ता एफडी, पीपीएफ, बिल भुगतान और रिचार्ज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से कई तरह के वित्तीय लेन–देन किए जा सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

इसके बाद इसमें अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना होगा। उपभोक्ता को मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। साथ ही उपभोक्ता को मोबाइल बैंकिंग पर्सनल वेरिफिकेशन नंबर सेट करना होगा। बाद में ओटीपी डलेगा। इसके बाद यह ऐप काम करना शुरू कर देगा।

सुकन्या और डिश का भुगतान भी होगा

इस ऐप के जरिये अकाउंट बैलेंस की जांच, अकाउंट स्टेटमेंट, करंट अकाउंट की चेकबुक के लिए आवेदन, बैंक में फंड ट्रांसफर, बिजली, पानी सहित अन्य बिल और मोबाइल पर डिश रिचार्ज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जमा, सुकन्या समृद्धि योजना की किस्त का भुगतान और एफडी भुगतान आदि की सुविधा ले सकेंगे।

अब बोतल पर 'शराब पीकर गाड़ी न चलाएं लिखना अनिवार्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों को शराब की बोतल पर एक नई चेतावनी लिखने के निर्देशों जारी किए गए है। अगर इन निर्देशों का पालन करने में कोई भी शराब विक्रेता कोताही करता हुआ पाया जाता है तो उसे विभागीय कार्रवाई का सामना करना होगा। अभी तक बोतल पर केवल इतना ही लिखा जाता रहा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन अब एक और चेतावनी बोतल पर लिखी जाएगी वो है, शराब पीकर गाड़ी न चलाए। माना जा रहा है कि इस चेतावनी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने में लोगों को जागरूक करने में सहायता मिलेगी तथा साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी होगी।

निर्देशों के मुताबिक पहली अप्रैल से शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं की चेतावनी वाली शराब की बोतलें बाजार में बिकेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी ठेका संचालक और शराब बनने वाली कंपनी पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार चाहे तो इसे स्थानीय भाषा में भी लिखवा सकती है।

युवाओं के लिए पुलिस में भर्ती होने का मौका, भरे जाएंगे 65 पद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

बेरोजगार युवाओं के लिए पुलिस में भर्ती होने का मौका है। प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 55 और वाहन चालकों के 10 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च से आरंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता हिमाचल का मूल निवासी होना चाहिए।

उसका नाम प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ड्राइवर पद के लिए आवेदक के पास भारी वाहन लाइसेंस होना अनिवार्य है। उन्होंने आवेदन करने को वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। वेबसाइट के हेल्प मेन्यू में जाकर भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

टीबी पर बेहतरीन काम में हिमाचल प्रथम

सात राज्यों को पछाड़ कर नॉर्थ जोन में जमाई धाक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश क्षय रोग के खात्मे पर हो रहे बेहतरीन कार्यों पर एक बार फिर मुहर लगी है। टीबी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम पर बेहतरीन काम के लिए हिमाचल सम्मानित हुआ है। हिमाचल ने नॉर्थ जोन में सात राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू–कश्मीर को पछाड़ कर यह अवार्ड हासिल किया है। यह खिताब टीबी टास्क फोर्स की एनुअल मीट के दौरान दिया गया। एनुअल मीट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 28 व 29 मार्च को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता संजीवा कुमार अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार ने की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव हिमाचल सरकार आरडी धीमान, राज्य क्षय रोग अधिकारी डा. आरके बारिया, प्रो. अशोक भारद्वाज चेयरमैन जोनल टास्क फोर्स व हिमाचल टास्क फोर्स सहित सभी मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्टेट टास्क फोर्स और नॉर्थ जोन के चेयरमैन प्रो. अशोक भारद्वाज ने बताया कि नॉर्थ जोन के आठ राज्यों में 98 सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, जो टीबी से लड़ने के लिए तकनीक और नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनुअल मीट में राज्य क्षय रोग अधिकारी डा. आरके बारिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कालेज में टीबी टेस्ट के लिए सीबीनेट मशीनें स्थापित कर दी गई है। नेरचौक कालेज में फिलहाल सीबीनेट मशीन नहीं है, यहां मशीन स्थापित कर दी जाएगी। स्टेट टीबी टास्क फोर्स के समन्वयक डा. अक्षय मिन्हास ने कहा कि ऐसे आबादी क्षेत्र तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो अभी भी सुविधाओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

हिमाचल में बोर्ड की निर्धारित पाठ्य पुस्तकें न पढ़ाने पर रद्द होगी संबद्धता

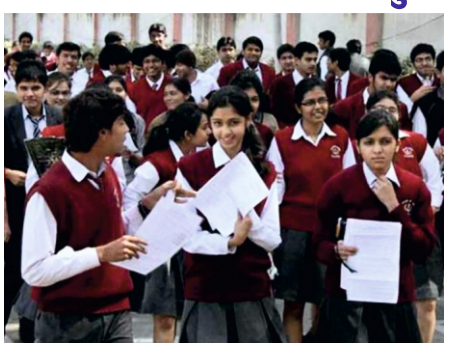

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल सरकार और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों में अब बोर्ड की निर्धारित पुस्तकें की पढ़ाई जा सकेंगी। निजी स्कूल मनमर्जी से निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना पाएंगे। इस शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी और राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली से जमा दो तक एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदने के अभिभावकों पर दबाव बनाने की लंबे समय से बोर्ड को शिकायतें मिल रही थीं।

स्कूल प्रबंधक मनमर्जी से निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकें पढ़ा रहे थे। इससे अभिभावकों को आर्थिक बोझ पड़ रहा था। ऐसे में अब बोर्ड ने पहली से जमा दो तक के सभी बच्चों को एनसीईआरटी और बोर्ड से निर्धारित और प्रकाशित पुस्तकें पढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूल प्रबंधक पुस्तकें बोर्ड के पुस्तक वितरण केंद्र, सूचना एवं मार्ग दर्शक केंद्र, क्षेत्र के पंजीकृत पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें खरीद सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2019–20 से सूबे के सभी स्कूलों में बोर्ड की निर्धारित पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

शैक्षणिक सत्र के बीच में विभाग और बोर्ड की टीमें स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि स्कूलों में बोर्ड की निर्धारित पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही हैं तो स्कूलों की संबद्धता नियमों के अनुसार रद्द की जाएगी।

हिमाचल के 54 शहरों में डोर टू डोर उठेगा कूड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के 54 शहरों में एक अप्रैल से डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को एनजीटी के आदेशों पर तुरंत अमल लाने को कहा है। इसके तहत लोगों को घरों में सूखा और गीला कचरा अलग–अलग रखना होगा।

एनजीटी के आदेश पर सरकार ने सभी शहरी निकायों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को शहर के हर घर से कूड़ा एकत्रीकरण योजना के तहत योजना तैयार कर इसे एक अप्रैल से लागू करने को कहा है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

सूबे में घरों से निकलने वाले कूड़े–कचरे का सही ढंग से निष्पादन करने में नगर निकाय असफल साबित हो रहे हैं। जिला कुल्लू में सात माह से सड़कों, चौक, चौराहों और नगर परिषद के पिटों में कूड़े के ढेर लगे हैं। अब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए डोर टू डोर योजना लागू करने को कहा है। एक अप्रैल से प्रदेश के दो नगर निगमों, 31 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों में लागू करने के आदेश जारी किए हैं। लोगों को अपने घर में सूखे और गीले कूड़े को अलग–अलग रखना होगा। दूसरा चरण सूबे की पंचायतों में शुरू होगा।

खुले में कूड़ा फेंका तो पांच हजार जुर्माना

हिमाचल शहरी विकास विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने बताया कि एक अप्रैल से सूबे के सभी 54 नगर निकायों में डोर टू डोर योजना के तहत कूड़ा उठाया जाएगा। इसको लेकर सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं। खुले में कूड़ा फेंकने पर एसडब्ल्यूएम नियम–2016 के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना होगा। शिमला में इसके बारे में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें शहरी विकास विभाग, टीसीपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे।

एमएमयू में बढ़ेगा एमबीबीएस का स्टेट कोटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में एमबीबीएस कोर्स के लिए फीस निर्धारण से जुड़े मामले में सुनवाई 30 अप्रैल के लिए टल गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य फीस निर्धारण कमेटी को आदेश दिए थे कि वह महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में एमबीबीएस कोर्स के लिए राज्य कोटा सीट व फीस के निर्धारण बाबत निर्णय ले और स्टेटस रिपोर्ट दायर करे।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में एमबीबीएस कोर्स के लिए स्टेट कोटे को 25 फीसदी से 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 30 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।

गलत प्रश्नों के मिलेंगे ग्रेस मार्क्स 8वीं और 9वीं के छात्रों को राहत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के निर्देश दिए हैं। इससे सूबे के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी।

वार्षिक परीक्षा के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में दोनों कक्षा के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग में कुछ गलती पाई गई है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड को शिकायतें आई थीं, जिस पर बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया है। बोर्ड ने आठवीं कक्षा के छात्रों को एक–एक नंबर के तीन प्रश्नों के ग्रेस नंबर और नौवीं कक्षा के छात्रों को दो प्रश्न के दो ग्रेस नंबर देने की हिदायत दी है। बोर्ड ने सूबे के 10 जिलों के उपनिदेशकों को ग्रेस नंबर देने बारे सर्कुलर जारी किया है।

पेड़ कटान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में पेड़ कटान पर सुप्रीम कोर्ट के पहले से जारी प्रतिबंध के आदेशों का सरकार अक्षरश पालन करे। यह आदेश प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने बीते 28 मार्च को प्रदेशसरकार को दिए।

खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों के निर्माण संबंधी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं ले लेती, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की जाए। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में किसी भी निर्माण कार्य के लिए पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश पारित किए हैं। 28 मार्च को सलापड़ से तत्तापानी को सड़क से जोड़ने वाले मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए हैं।

इस मामले में अधीक्षक अभियंता मंडी ने कोर्ट को बताया था कि इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 21 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसके लिए केंद्र से स्वीकृति ली जानी बाकी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इस बारे केंद्र से तुरंत संपर्क करे। इस सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने हाईकोर्ट के समक्ष बयान दिया कि सड़क का निर्माण कार्य अगले छह महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अधीक्षक अभियंता मंडी ने शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को यह भी बताया कि नेरी गांव में 70 मीटर स्टील के पुल का निर्माण कार्य का काम ठेकेदार संजय कुमार शर्मा को दिया गया था और इस पुल के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उसने 15 सितंबर 2018 तक का समय मांगा था। लेकिन समय समय पर निर्देश दिए जाने के बावजूद भी उसने पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया।

क्या है मामला

हाईकोर्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश न होने के कारण खंडपीठ ने संजय कुमार शर्मा को 50 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई और आदेश दिए कि राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में चार सप्ताह के भीतर जमा करवाई जाए अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेश दिए गए कि वह शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताए कि इस पुल का निर्माण कार्य कितने समय में पूरा किया जाएगा। मामले की आगामी सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है।

सलापड़ से तत्तापानी को जोड़ने वाली सड़क का काम 1980 में शुरू हुआ लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण स्थानीय लोग सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। वर्तमान में सलापड़ से तत्तापानी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है जो की इस सड़क के निर्माण के बाद केवल 67 किलोमीटर रह जानी थी। लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण 32 वर्ष में केवल 16 किलोमीटर सड़क ही बन पाई। इसके बाद से लंबित कार्य को पूरा करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

योजनाबद्ध तरीके से किया गया हमला !

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसएफआई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ हुई खूनी झड़प सुनियोजित तरीके से थी । पुलिस जांच में इसका खुलासा हो चुका है। पुलिस में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एक छात्र विकास ने आरोप लगाया कि एसएफआई के कुछ कार्यकर्ता उसके कमरे में आए और रातभर बंद करके रखा। यहीं नहीं उसे पीटा था। विकास ने बताया कि उससे पूछा था कि सुबह ग्राउंड में आरएसएस की शाखा कब लगती है। इसके बाद विकास को कमरे में बंद कर दिया। आरोप लगाया कि एसएफआई के कार्यकर्ता रात को दो तीन बार उसके कमरे में आते रहे। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि हमला सुनियोजित था।

शिमला : पुलिस ने देर रात आठ एसएफआइ कार्यकर्ता किए गिरफ्तार, एचपीयू में तनाव

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल के नजदीक हुई एसएफआई और आरएसएस के स्वयंसेवकों की खूनी झड़प के बाद पुलिस ने देर रात आठ एसएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफतार किया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवि में वीसी का घेराव कर लिया है व आरोपित कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। एचपीयू में माहौल तनावपूर्ण हो गया है व छावनी में तबदील हो गई है। इस वारदात में करीब 15 छात्र घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, शाखा लगाने को लेकर एसएफआई के छात्रों से पहले कहा सुनी हुई और कुछ ही देर में बात खूनी लड़ाई तक पहुंच गई। विवि परिसर एक बार फिर तनाव से भर गया। पुलिस ने मामला दर्ज छानबीन शुरू कर दी। जांच चल रही है ।

एपीजी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ्य जीवन की निशानी: प्रो. कुलकर्णी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्थानीय अलख प्रकाश गोयल (एपीजी) शिमला विश्वविद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट द्वारा इस अभियान की अगुवाई की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसएन कुलकर्णी ने स्वच्छता अभियान के बारे में विद्यार्थियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का असर समूचे देश में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आस–पास के वातावरण को स्वयं स्वच्छ रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास का वातवरण स्वच्छ है तो उसका असर आपके स्वस्थ्य पर भी पड़ता है। प्रो. कुलकर्णी ने कहा कि स्वच्छता आपको सकारात्मक सोच की परिचायक भी बनती है। आसपास की गंदगी से आपकी सोच को भी प्रभावित करती है। विश्वविद्यालय में चलाए गए स्वच्छता अभियान में देश–विदेशी छात्रों ने बढ़ चढकर भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने स्वच्छता के संदेश देते बैनर तथा स्लोगन लिखे पोस्टर भी हाथों में उठाए हुए थे। इस अभियान में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग ने भी बच्चों के साथ कचरा एकत्रित किया। विश्वविद्यालय में एनएसएस के समन्वयक अमित नाम्टा ने कहा कि हमारी यूनिट समय–समय पर समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियां करते रहते हैं। इसमें एनएसएस के सभी कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत यूनिट के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर को साफ तथा स्वच्छ रखने का प्रण लिया। इस मौके पर सभी विषयों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया।

तपने लगे हिमाचल के पहाड़ ऊना से ज्यादा गर्म हुआ शिमला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में मैदानों के साथ–साथ पहाड़ भी तपने लगे हैं। हिल्स क्वीन शिमला का न्यूनतम पारा सबसे गर्म जिले ऊना से भी अधिक हो गया है। मौसम में आए बदलाव के चलते पहाड़ों में भी पसीने छूटने लगे हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 14.5, जबकि ऊना का 14 डिग्री सेल्सियस रहा। इस साल में शिमला शहर का यह सबसे अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है।

हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा के बाद शिमला का न्यूनतम पारा पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। शुक्रवार को ऊना का अधिकतम पारा 34.2 डिग्री रहा ।

स्कूलों के बाहर रोज लग रहा जाम, पुलिस भी मेहरबान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सर्कुलर रोड पर स्थित शहर के नामी स्कूल बच्चों से मोटी फीस तो वसूल रहे हैं, लेकिन उन्हें स्कूल से लाने और ले जाने के लिए चल रही गाड़ियों के लिए पार्किंग तक की सुविधा नहीं दे रहे। रोज सुबह आठ से लेकर दस और शाम तीन से पांच बजे इन स्कूलों के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। अकेले सेंट एडवर्ड स्कूल के बाहर रोज 60 से ज्यादा गाड़ियां पहुंचती हैं जिनसे लंबा जाम लगता है। इनमें बच्चों को छोड़ने के लिए आने वाली अफसरों और नेताओं की गाड़ियां भी शामिल हैं जो सर्कुलर अवैध पार्किंग कर जाम लगाती हैं।

पुलिस इनके आगे बेबस नजर आती है। इनके न तो चालान कटते हैं और न ही कोई कार्रवाई होती है। सर्कुलर रोड पर हिमलैंड, लॉन्गवुड, नवबहार और ताराहॉल के समीप रोज लंबा जाम लगता है। ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों के पास पार्किंग के लिए जगह नहीं। लेकिन ये पार्किंग की सुविधा देना ही नहीं चाहते। नगर निगम ने इन स्कूलों में पार्किंग स्थल चिन्हित करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसने सुझावों में जिक्र किया है कि कैसे इन स्कूलों के कैंपस में ही पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है। निगम ने कई महीने पहले स्कूलों को ये सुझाव दिए थे। लेकिन स्कूल है कि मानते नहीं।

10 दिन में पार्किंग का प्रबंध न कियातो बंद कर देंगे एडवर्ड स्कूल: हाईकोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप शिमला शहर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित यातायात मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि अगर सेंट एडवर्ड स्कूल नगर निगम शिमला की ओर से गठित कमेटी के सुझावों पर 10 दिन के भीतर अमल नहीं करता है तो चालू शैक्षणिक सत्र में अस्थायी तौर पर स्कूल बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है।

यह आदेश तब तक जारी रह सकते हैं, जब तक पर्याप्त पार्किंग स्थल का इंतजाम नहीं किया जाता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह आदेश पारित किए हैं।

कोर्ट ने शिमला के अन्य स्कूलों जीसस एंड मेरी स्कूल, नाभा, लोरेटो कान्वेंट तारा हॉल, चेप्सली और ऑकलैंड हाउस स्कूल से भी कमेटी के सुझाए पार्किंग स्थल और यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने संबंधित सुझावों पर अमल करने को कहा है।

गौरतलब है कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को यातायात व्यवस्था सुचारु चलाने के लिए उचित कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे, जिस पर नगर निगम ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

एडवर्ड स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गठित कमेटी के सुझावों की अनुपालना में हाईकोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।

नाकेबन्दी के दौरान 3.26 लाख की नकदी व 971.053 लीटर शराब जब्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस, आबकारी तथा आयकर विभाग द्वारा गठित दस्तों द्वारा आज प्रदेश में की गई संयुक्त नाकेबन्दी के दौरान 3,26,485 रूपये की नकदी, 971.053 लीटर शराब, बीयर तथा लाहण इत्यादि के अतिरिक्त 0. 005001 किलोग्राम हेरोईन तथा 0.12556 किलोग्राम चरस जब्त की गई।

पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 मार्च तक पुलिस के पास 4717 लाईसेंस प्राप्त हथियार जमा हुए और अब प्रदेश में कुल 51,929 हथियार जमा किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित 21 व्यक्तियों की पहचान की गई और अब तक कुल 1154 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि आज उनके कार्यालय में प्राप्त कुल 7 शिकायतों में सभी शिकायतें आम जनता से प्राप्त हुई और अब तक प्राप्त कुल 97 शिकायतों में से 38 का निपटारा कर दिया गया है और शेष 59 शिकायतें सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्रवाई हेतु भेजी गई हें।

उन्होंने बताया कि जिलों में भी कुल 50 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 24 का निपटारा किया जा चुका है और शेष 26 शिकायतों में कांगड़ा जिला 7, मण्डी 5, शिमला 1, हमीरपुर 4, ऊना 3, बिलासपुर 3, सोलन 2 तथा सिरमौर जिला में 1 शिकायत शामिल हैं।

मिशन रीव देगा घर द्वार पर रोजगार के अवसर

युवाओं को एनएसडीसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है । एन एस डी सी से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स के बाद रीव के अंतर्गत सर्विस एसोसियेट के पदों को भरा जाना है जिसकी प्रक्रिया शुरु हो चुकी है । ज़िला शिमला में भी युवाओं में इस प्रशिक्षण के लिए ख़ासा उत्साह दिख रहा है । मिशन रीव चयनित युवाओं के लिए एन एस डी सी से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्रशिक्षण करवाऐगा तथा प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाऐंगें । यह प्रशिक्षण ऑनलाईन होगा जिसके लिए निर्धारित शुल्क 8000/ रुपये हैं । इसके अलावा प्रशिक्षु के पास एक टैबलेट होना आवश्यक है जिसकी उपलब्धता मिशन रीव द्वारा की जाएगी यदि प्रशिक्षुओं के पास स्वयं का टैबलेट नहीं है । इसके लिए 12000/ रुपये देय होंगे । इसके अलावा तीन दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण के लिए 5000/रुपये निर्धारित है जिसमें प्रशिक्षु के आने–जाने, रहने, भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था होगी । प्रशिक्षण के लिए एन एस डी सी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाऐगा । प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को एक निश्चित रोजगार हेतु नियुक्ति पत्र दिए जाऐंगे । शिमला ज़िले में भी इसके लिए युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है ।

हिमाचल को 2021 तक टीबी रोग मुक्त करने का लक्ष्य

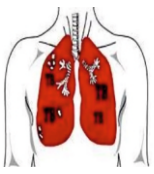

World TB Day

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 2025 तक टीबी रोग मुक्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं। हिमाचल सरकार भी वर्ष 2021 अंत तक सूबे को टीबी रोग मुक्त करने का प्रयास कर रही है।

हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य हैं, जहां सभी जिला केंद्रों के अस्पतालों के अलावा कुछ उपमंडल स्तर के अस्पतालों में भी संभावित टीबी रोगियों के बलगम की जांच होती है। सीवीनेट में मरीज की बलगम में अगर एक भी कीटाणु टीबी रोग का होगा, वह भी जांच में पकड़ में आता है।

उधर, राज्य क्षय रोग कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार आने वाले दिनों में टीबी रोग की जांच के अभियान को और गति दी जाएगी। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रमों में भी तेजी जाने तक काम हो रहा है।

सूबे में टीबी रोग की जागरूकता को स्वास्थ्य विभाग ने इसी महीने टीबी मुक्त हिमाचल अभियान नाम से एक मोबाइल एप लांच किया। मई 2019 तक सूबे के 35 और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में माइक्रोस्कोपी सेंटर खोले जाएंगे।

पंचायत स्तर पर फोरम गठित की जाएगी। पहले पंचायत, फिर खंड और जिला को टीबी रोग मुक्त किया जाएगा। फिर से घर–घर जाकर लोगों की जांच के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा जो टीबी रोगी ठीक हुए हैं, उन्हें भी लोगों को जागरूक करने के मुहिम में जोड़ा जा रहा है।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के पास टीबी रोग के लगभग 17 हजार नए मामले सामने आते हैं। कांगड़ा जिला के पालमपुर में विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें स्कूल–कॉलेज के विद्यार्थियों की रेड एरो प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा।

आंकड़े

बिलासपुर	488
चंबा	1118
हमीरपुर	772
कांगड़ा	3461
किन्नौर	110
कुल्लू	1449
लाहौल–स्पीति	18
मंडी	2370
शिमला	2852
सिरमौर	861
सोलन	2223
ऊना	750

MISSION RIEV
रोजगार का सुनहरा अवसर
MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages
CERTIFIED NSDC TRAINING
सर्विस एसोसिएट के पदों को भरने कि लिए प्रशिक्षण
प्रशिक्षण हेतु NSDC द्वारा विद्या कौशल लोन सुविधा
इसमें शामिल होगा (तकनीकि शुल्क –8000/–, टैबलेट 12000/–
3 दिन का संस्थागत प्रशिक्षण–5000/–)
आवेदन करें
www.missionriev.in
www.recruitment.missionriev.in
प्रथम बैच 15 अप्रैल से आरम्भ
योग्यता 12वीं पास या समकक्ष
1 मई से नियुक्ति, मासिक आय 10,000 हजार से 18,000
200 घन्टें का NSDC मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण
LAST DATE 12 April 2019
For Detail : 01772843528/2844073, 9816741687, 7876052696, 82196 94079, 7018537413 T&C Apply*
MISSION RIEV SECRETARIAT, IIRD COMPLEX, BY PASS ROAD, SHANAN, SHIMLA-6, HIMACHAL PRADESH

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

आग्नेय शस्त्र जमा नहीं कराए तो होगी ठोस कानूनी कार्रवाई

रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

आग्नेय शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री जमा कराने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। हालांकि, सिरमौर पुलिस कई जगह घरद्वार जाकर लाइसेंस धारकों से बंदूकें जमा करने का कार्य कर रही है। बावजूद इसके अभी तक आग्नेय शस्त्र जमा कराने का कार्य 45 फीसदी ही हो पाया है। जिले में कुल 8316 लाइसेंसी बंदूकें पंजीकृत हैं। अभी तक करीब 33 सौ बंदूकें ही नजदीकी पुलिस थानों में जमा हो पाई हैं। लाइसेंसी बंदूकें जमा न करवाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे लाइसेंस धारकों के खिलाफ पुलिस सीधे ही मामला अदालत में पेश करेगी। इसमें सजा का भी प्रावधान है। आदर्श आचार संहिता के तहत जिला प्रशासन समेत पुलिस महकमे ने पहले ही लाइसेंस धारकों को बंदूकें जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग ने और चौकियों में लाइसेंस धारकों को बंदूकें जमा कराने के लिए मुहिम भी चलाई है। कई स्थानों पर पुलिस लोगों के घर-घर पहुंच रही है। पुलिस मौके पर ही बंदूक लेकर रसीद जारी कर रही है।

जागरुकता का अभाव भी वजह

अभी तक यह बात सामने आई है कि जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सूचना और जागरूकता का अभाव भी है। वहीं, कई लाइसेंस धारक समय और धन की बरबादी की वजह से समय पर अपने हथियार जमा नहीं करवा रहे हैं। कई लोगों को अपना हथियार लेकर थाने तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। ऐसे में समय भी बरबाद होता है। इसके चलते भी लोग आग्नेय शस्त्र जमा कराने में लेटलतीफी कर रहे हैं।

इन पर लागू नहीं हैं आदेश

सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री और होमगार्ड जवानों पर यह आदेश लागू नहीं हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है

ऐसे व्यक्तियों के बारे में पुलिस पुनः आकलन करेगी। यदि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में जान का खतरा है तो उस स्थिति में यह आदेश उन पर भी लागू नहीं होंगे।

ठोस कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि लाइसेंसी बंदूकें आदि जमा न करवाने वालों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि समय पर लोग अपने हथियार जमा नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ मामले अदालत में भेजे जाएंगे। उन्होंने सभी लाइसेंसधारकों से आग्रह किया कि जल्द वे अपने हथियार नजदीकी पुलिस थानों में जमा करवाएं। पुलिस भी घर-द्वार जाकर हथियार जमा कर रही है।

15 अप्रैल से वन कर्मियों की छुट्टियां बंद

रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

गर्मियों की दस्तक के चलते वन विभाग ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इस कड़ी में जहां जंगलों को आगजनी से बचने के लिए विभिन्न रेंज में टीमें गठित की गई हैं, वहीं फायर सीजन के चलते वन कर्मियों के अवकाश भी रद्द करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। आगामी 15 अप्रैल के बाद कोई भी वन कर्मी छुट्टी नहीं ले पाएगा। जानकारी के मुताबिक पांवटा वन मंडल में भी गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आगजनी को रोकने के लिए विभाग द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डीएफओ पांवटा वन मंडल के मुताबिक गत वर्ष की तरह इस साल भी जंगलों की आग से निपटने के लिए विभाग ने प्रबंध पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष में भी पांवटा वन मंडल में इस तरह आगजनी के कुछ मामले सामने आए थे

जिनसे बहुत कम नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि इस बार भी पिछली बार की तरह टीम वर्क कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में मंडल के सभी रेंज कार्यालयों के प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि एक्शन टीमों का जल्द गठन किया जाए। इन टीमों में जहां कुछ वन विभाग के कर्मी होते हैं, वहीं कुछ स्थानीय लोगों व समाजसेवा से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। यह टीम जंगल पर नजर रखती है तथा यदि कहीं आगजनी की सूचना मिलती है तो तुरंत हरकत में आकर आग बुझाने का कार्य करती है।

सैकड़ों छात्रों के परीक्षा केंद्र इधर से उधर

रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के केंद्र इस बार शिक्षा खंड से बाहर अथवा इधर-उधर किए जाने से सैकड़ों छात्रों व अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। 6 अप्रैल को होने वाले इस प्रवेश परीक्षा में अधिकतर छात्रों के एग्जामिनेशन सेंटर उनके गृह शिक्षा खंड की बजाय दूसरे ब्लॉक में दिए गए हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा के फार्म भर चुके छात्रों के दो दर्जन अभिभावकों ने कहा कि जेएनवी संस्थान की गलती की वजह से उन्हें अपने बच्चों को 50 से 80 किलोमीटर दूर एग्जाम के लिए ले जाना पड़ेगा। कुछ परीक्षा केंद्रों के लिए तो बस में एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। शिक्षा खंड संगड़ाह के 100 के करीब छात्रों के परीक्षा केंद्र नौहराधार व ददाहू आदि स्थानों पर रखे गए हैं, जबकि इन दोनों शिक्षा खंडों में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है। विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवोदय के 10 परीक्षा केंद्र बंद होने के चलते तथा संस्थान द्वारा इस बार कम्प्यूटराइज तरीके से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किए जाने के चलते ऐसा हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी संगड़ाह रविंद्र चौहान के अनुसार इस बार इस शिक्षा खंड मुख्यालय में पिछले वर्ष से कम छात्रों के ही रोल नंबर आए हैं।

हरिपुरधार को चूड़धार से जोड़ने की योजना अधर में

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सिरमौर जिला के दो धार्मिक पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए मां भंगायनी सेवा समिति ने करीब दो वर्षों पहले एक बड़ी योजना तैयार की थी। समिति ने हरिपुरधार को चूड़धार से जोड़ने के लिए हरिपुरधार से चूड़धार तक लगभग 30 किमी लंबा रज्जू मार्ग बनाने की योजना तैयार की थी। इस मार्ग पर पर्यटकों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छिंडीयारा व तोटा बाक्टा नामक स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस दो वेस कैंप बनाने की भी योजना बनाई थी। समिति ने इस योजना का पूरा प्रपोजल तैयार किया था। समिति ने प्रपोजल को मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग व सरकार को भेज दिया था, मगर सरकार की ओर से समिति को अभी कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

दुकानों-ढाबों से पकड़े 13 घरेलू सिलेंडर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने बीते दिनों सोलन-कंडाघाट नेशनल हाई-वे पर स्थित दुकानों व ढाबों को औचक निरीक्षण किया। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने इस दौरान दो दर्जन से अधिक दुकानों व ढाबों का निरीक्षण किया और व्यवसायिक उपयोग में लाए जा रहे 13 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया। वहीं, एक दुकान से एक किलो प्रतिबंधित पोलिथीन बरामद होने पर तीन हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। विभागीय अधिकारियों को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सोलन से कंडाघाट मार्ग पर स्थित कई दुकानों व ढाबों पर घरेलू सिलेंडरों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सोलन के चंबाघाट से आरंभ हुआ यह निरीक्षण कंडाघाट तक जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों में रेट लिस्ट सहित सिलेंडरों व पोलिथीन की चौकिंग की। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया की कई दुकानों व ढाबों पर घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने 13 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया। इसके अलावा एक दुकान से एक किलोग्राम प्रतिबंधित पोलिथीन भी बरामद किया गया और उससे मौके पर ही तीन हजार रुपए जुर्माना वसूला।

ढाबे में आग, 1.70 लाख नुकसान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

नालागढ़ बद्दी एनएच मार्ग पर पीरस्थान के समीप डाडीभोला स्थित एक ढाबे में अचानक लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अज्ञात कारणों से लगी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड नालागढ़ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक ढाबे को इस आग से एक लाख 70 हजार रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से आसपास की अन्य करीब दो करोड़ की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार नालागढ़ बद्दी एनएच मार्ग पर डाडीभोला स्थित भाटियां के धुंधली निवासी गुरचरण सिंह के ढाबे में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से तीन सिलेंडर, बरतन, काउंटर, कुर्सियां, मेज, राशन आदि जल गए और साथ में खड़ा एक बाइक (एचपी-12जे-8372) को भी नुकसान हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग ने जिला में शुरु की डेंगू से निपटने की तैयारियां

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक डेंगू का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस बार बदलते मौसम को देखते हुए विभाग ने पहले ही खुद को तैयार करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को डेंगू पर जागरूक करना शुरू कर दिया है। वहीं विभाग ने डेंगू से संबंधित छिड़काव वाली दवाइयों सहित डेंगू के होने वाले टेस्ट किट भी मंगवा ली हैं।

जानकारी के अनुसार डेंगू गर्मी और बारिश के मौसम के दौरान अधिक फैलता है।

पिछले साल डेंगू के जिला भर में 1695 मामले दर्ज किए गए थे।

अब बिना भूमि प्लज किए दो लाख का ऋण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

हिमाचल में किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेना आसान हो गया है। किसानों को क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण लेने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। किसान को अब किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा दो लाख रुपए तक का ऋण लेने के लिए अपनी भूमि प्लज नहीं करवानी पड़ेगी।

एनएच-पांच पर दरकी पहाड़ी, स्कूल को खतरा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

कालका-शिमला नेशनल हाई-वे पांच पर जाबली के समीप पिछले दिनों भू-स्खलन हो गया। भू-स्खलन होने से भारी मात्रा में सड़क पर पत्थर व मलबा सड़क पर गिरा। पहाड़ी के दरकने से हाई-वे के साथ ही बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल राजड़ी (जाबली) काभवन खतरे की चपेट आ गया है। यही नहीं पिछले दिनों स्कूल में ग्राउंड में दरारें ओर गहरी हो गई। इसके यहां पर पढ़ रहे बच्चों व कार्यरत स्टाफ को यहां डर सताने लग गया है। वहीं, सनवारा के समीप लगातार मलबा आने से नेशनल हाई-वे पर जाम की स्थिति भी बन रही है।

कालका-शिमला नेशनल हाई-वे पर फोरलेन को लेकर कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान कंपनी द्वारा मौसम को देखते हुए फिर से कटिंग का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। कटिंग कार्य के चलते हाई-वे पर राजड़ी स्कूल के ग्राउंड में दरारें आ गई है। इसके कारण विद्यार्थी ग्राउंड में खेलने से भी घबरा रहे है। राजड़ी स्कूल में पहली से बाहरवीं कक्षा तक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते है। लेकिन कटिंग के कारण पड़ रही दरारों से विद्यार्थियों में डर का भय बना रहता है। देर रात्रि स्कूल के एक-ब्लॉक के नीचे भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान गनीमत रही कि नीचे हाई-वे पर गुजर रहे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अचानक हुए लैंडस्लाइड से स्कूल के प्रिंसीपल कार्यालय, अधीक्षक कार्यालय व उसके ऊपर बने कमरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए इन कमरों को खाली किया जा रहा है।

नालागढ़ में 110 पोलिंग बूथ, 13 संवेदनशील, 10 अतिसंवेदनशील

द रीव टाइम्स ब्यूरो

19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नालागढ़ व दून विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों को संवेदनशील व अति संवदेनशील श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है। नालागढ़ में कुल 110 पोलिंग बूथों में से 10 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं, जबकि 13 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, जबकि 87 सामान्य पोलिंग बूथ बनाए गए है, जबकि दून विस क्षेत्र के तहत 93 पोलिंग बूथों में से 15 अतिसंवेदनशील और 11 संवेदनशील बूथ है, जबकि 67 पोलिंग बूथ सामान्य हैं। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के तहत दो विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ और दून आते हैं और यह दोनों ही विस क्षेत्र पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा की सीमाओं के साथ सटे हुए हैं। नालागढ़ विस क्षेत्र के 10 अति संवेदनशील क्षेत्रों में नंड, बैरछा, बघेरी, मस्तानपुरा, गुल्लरवाला करसौली-एक और दो, नालागढ़ शहर का वार्ड-सात, राजपुरा, रंगूवाल-एक व दो शामिल हैं, जबकि 13 संवेदनशील पोलिंग बूथों में जोघों, रामपुर-एक, जोघों बनियाला, पंजैहरा-एक, बरुणा-एक, नंगल उपरला, भाटियां-एक और दो, दभोटा-एक व दो, ढाणा, मंझौली-एक व दो शामिल है। दून विधानसभा क्षेत्र के तहत 15 अति संवेदनशील बूथों में लोदीमाजरा, पटटा, भटौलीकलां, मलकूमाजरा, मानपुरा-एक, किशनपुरा-एक, भुड्ड, शीतलपुर बद्दी, बद्दी-दो, सराजमाजरा, बिलांवाली लबाणा-एक और दो, बरोटीवाला-एक, लबाणा मंधाला-एक व सेरां शामिल है, जबकि संवेदनशील 11 बूथों में साई, सालगा, थाना-एक, मखनूमाजरा, लेही, कडुआना-एक, गुल्लरवाला, संडोली-एक, बद्दी-एक, झाड़माजरी व कैंबावाला शामिल है।

ऊना में 82 नकलचियों के बनाए केस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

ऊना जिला में हिमाचल बोर्ड द्वारा स्थापित किए परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख का पहरा होने के बावजूद नकल का खेल चलता रहा। शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वायड टीमों ने छह मार्च से 22 मार्च तक चली बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के करीब 82 मामले पकड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा 21 नकल के मामले अंग्रेजी विषय में छात्रों को नकल करते हुए दबोचा है। वहीं, दसवीं के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में 12 विद्यार्थी पर्ची लगाते हुए पकड़े गए हैं। दसवीं व जमा दो के हिंदी विषय में दस, अर्थशास्त्र में नौ तथा गणित की परीक्षा में आठ विद्यार्थियों को नकल करते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। जबकि बोर्ड अन्य विषयों की परीक्षाओं में करीब 22 विद्यार्थियों को नकल करते पकड़ा गया है। फ्लाइंग स्क्वायड में तैनात अधिकारियों व शिक्षकों का कहना है कि सीसीटीवी लगाने से नकल पर पहले से करीब 40 फीसदी तक रोक लगी है, लेकिन कुछ शरारती बच्चे होते हैं। जो कि परीक्षा से संबंधित मैटीरियल अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाते हैं। जिला में नकल के अभिशाप को खत्म करने के लिए सख्ती की जा रही है। इसी का नतीजा है कि अभी तक 80 से अधिक नकल के मामले पकड़े जा चुके हैं, जिनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

डंपिंग साइट का कार्य फिर अधर में आचार संहिता के चलते रुके कई कार्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत में शामिल बैजनाथ पपरोला नपं के करोड़ों के विकास कार्यों पर चुनावी आचार संहिता का प्रतिकूल असर पड़ा है। नपं के गठन के बाद से 11 वार्डों के कूड़े–कर्कट को ठिकाने लगाने लिए बनने वाली डंपिंग साइट का कार्य अधर में लटक गया है। हाल यह है कि डंपिंग साइट के अभाव में कूड़े–कर्कट को नियमों के खिलाफ विनबा खड्ड के समीप जलाया जा रहा है इससे पर्यावरण के साथ खड्ड का पानी भी दूषित हो रहा है। इसी प्रकार नपं के तहत विभिन्न वार्डों में स्थापित होने वाली 450 एलईडी और सोलर लाइटों का कार्य भी आगे नहीं बढ़ सका है। खीर गंगा घाट के समीप दो करोड़ रुपये से तैयार होने वाली पार्किंग का कार्य शिलान्यास और बजट के बावजूद अधर में लटक गया है। तीन वार्डों में बनने वाले पार्क में से दो के टेंडर होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसके अलावा चार करोड़ के नपं के ग्यारह वार्डों के 98 रास्तों के लिए टेंडर होने के बावजूद उनको रद्द करना पड़ा है। हालांकि इन रास्तों के टेंडर के रद्द होने के पीछे पर्याप्त बजट न होना भी एक कारण रहा है, लेकिन अब बजट होने के बावजूद इन रास्तों के टेंडर आचार संहिता के बाद ही हो सकेंगे।

खस्ताहाल सड़क और नाले की बदबू से परेशान हैं राजगढ़वासी

कंकरीट से बनी सड़क बदहाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

नगर परिषद देहरा के वार्ड नंबर एक राजगढ़ की आबादी करीब 1100 है। इस वार्ड में प्रवेश करने के साथ ही राहगीरों का सामना उपमंडलीय आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ बहते नाले के गंदे पानी की बदबू के साथ होता है। इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

राजगढ़ को जाने वाली सड़क कंकरीट की बनी हुई है, लेकिन वह धीरे–धीरे उखड़ रही है और सड़क पर छोटे–छोटे पत्थर बिखरे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। साथ ही सड़क किनारे नालियों में खड़ा गंदा पानी सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। यहां पर काफी समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है। कई जगह पर तो नालियां हैं ही नहीं, इस कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर बहता है। जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। राजगढ़ वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड में सड़क किनारे नालियों की सफाई गर्मियों से पहले नहीं हुई तो मक्खी और मच्छरों के चलते जीना मुहाल हो जाएगा।

नशीला दूध बेचने वालों पर विभागीय कार्रवाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

सुजानपुर पुलिस ने मेला ग्राउंड में दूध के नाम पर लोगों को नशीला पदार्थ बेचने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई में ऐसे धंधे करने वाले सभी स्टाल मेला ग्राउंड से हटवा दिए गए हैं। भविष्य में उन्हें इस तरह का कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करने को कहा गया है। सुजानपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोग खुश हैं। सुजानपुर होली मेला ग्राउंड में बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग सुजानपुर में औचक निरीक्षण करते हुए कुछेक दूध बेचने वाले स्थान पर पहुंचकर जांच–पड़ताल की थी। इस दौरान खुद खंड स्वास्थ्य अधिकारी ने 20 रुपए देकर एक स्पेशल दूध का गिलास लिया था, जिसमें दूध बेचने वाले दुकानदार ने हरे रंग का पदार्थ मिलाकर उन्हें दिया, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने बोतल में डालकर अपने कब्जे में ले रखा है और उसकी जांच करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उधर स्वास्थ्य विभाग के इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग सुजानपुर सतर्क हो गया है। विभाग की टीम ने मेला ग्राउंड में पहुंच कर ऐसे सभी दूध बेचने वालों को वहां से हटवा दिया है और उनके द्वारा जो दूध बेचा जा रहा था उसे भी फिंकवा दिया है।

भंजवाणी पुल को छिड़ेगा जागरुकता अभियान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

गोबिंदसागर पर भंजवाणी पुल निर्माण को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि यह पुल लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लोग इस मसले पर एकजुट होकर लामबंद हो गए हैं और अब हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में भंजवाणी पुल पुनर्निर्माण समिति की बैठक पंचायत घर बल्हभलवाणा के प्रांगण में समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एकमत से पुल निर्माण किए जाने की मांग की तथा निर्णय लिया कि क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए शीघ्र ही समिति एक जागरूकता अभियान चलाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व प्रधान जगतराम शर्मा, हीरापुर पंचायत प्रधान सुरेशा शर्मा, पीआर चौहान, कृष्णलाल चौहान, बासुदेव, कृष्णू राम वर्मा और भाग सिंह धीमान आदि ने कहा कि भंजवाणी का यह पुल राजा अमर चंद ने 1889 में बनवाया था। उस समय जिला बिलासपुर में सतलुज नदी पर यही एक मात्र पुल था, जिसके माध्यम से सतलुज पार के लोग कहलूर रियासत के मुख्यालय पहुंचते थे।

राज्य स्तरीय महोत्सव के आयोजन के लिए कमेटियां गठित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

राज्य स्तरीय कालेश्वर महादेव बैसाखी महोत्सव 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। अध्यक्ष मेला समिति एवं उपमंडल अधिकारी (ना) धनवीर ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेले में गौरवमयी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कालेश्वर में मेला समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में महोत्सव को गौरवमयी ढंग से संपन्न करने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए अलग–अलग कमेटियों का गठन किया गया, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मेले के दौरान जनता के मनोरंजन के लिए 13 और 14 अप्रैल को रंगारंग सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। संध्याओं में स्थानीय लोक कलाकारों के अलावा प्रदेश के जाने माने लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों का मनोरंजन करेंगे।

एनजीटी की टीम ने किया नादौन बाजार का दौरान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

नादौन–ज्वालामुखी मार्ग पर स्थानीय उपडाकघर के निकट दुकानदारों ने एनजीटी की चेयरपर्सन राजवंत संधू के काफिले को रोककर यहां की सफाई व्यवस्था तथा अन्य समस्याओं बारे विस्तार से बताया। यह दुकानदार सुबह से ही टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टीम पहुंची नादौन में सफाई व्यवस्था व अन्य समस्याओं बारे दुकानदारों ने उन्हें अवगत करवाया। एनजीटी टीम प्रतिनिधियों ने उनकी बात सुनी और साथ चल रहे विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का समाधान करवाएं। दुकानदारों ने बताया कि ब्यास नदी में शहर की गंदगी काफी मात्रा में घुल रही है, जिसे रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि नादौन बस अड्डा से लेकर ब्यास पुल तक गंदे पानी की निकासी के लिए कई वर्ष पूर्व सीवरेज डाली गई है, परंतु अभी तक भी यह पूरी तरह से चालू नहीं है। उन्होंने बताया कि कई जगह इसका निर्माण अधूरा पड़ा है। इस कारण उनकी दुकानों के आगे बनाई गई गहरी नालियों में गंदा पानी हर समय जमा रहता है। इससे न केवल प्रदूषण फैल रहा है, बल्कि बदबू के कारण ग्राहक भी उनकी दुकानों में आने से कतराते हैं। संधू ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि इस बारे शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे।

अप्रैल में जारी होगी डिफाल्टरों की लिस्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

अप्रैल में तीन महीने बाद बिजली बोर्ड के डिफाल्टरों की सूची निकलेगी। अप्रैल में एक साथ सैकड़ों डिफाल्टरों को नोटिस निकालने की तैयारी हो रही है। पहले सप्ताह में ही डिफाल्टरों की सूची तैयार कर संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं को सौंपी जाएगी। इसके बाद डिस्कुनेक्शन अभियान शुरू होगा। फिलहाल बोर्ड के नए सॉफ्टवेयर टीसीएस ने नियमित कार्य करना शुरू कर दिया है। नए सॉफ्टवेयर के कारण ही तीन महीने तक डिफाल्टर बचे रहे। अब इन पर विभागीय कार्रवाई होगी। कई डिफाल्टरों के स्थायी कनेक्शन काटे जाएंगे। चार से पांच माह से बिजली बिलों का भुगतान न करने वालों के स्थाई बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं। वहीं कई लोगों के टेंपरेरी कनेक्शन कटेंगे। बोर्ड की माने तो डिफाल्टरों की संख्या हजार से ऊपर हो सकती है। पहले सप्ताह ही इस बात का पता चलेगा। जाहिर है कि विद्युत बोर्ड हर माह डिफाल्टरों की सूची जारी करता है। इसके बाद इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होती है। बीते करीब तीन माह पहले बोर्ड के सॉफ्टवेयर को बदला गया है। टीसीएस के माध्यम से अब सारा काम किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के नियमित रूप से संचालित होने में काफी समय लग गया। इस कारण डिफाल्टरों की सूची जारी नहीं हो पा रही थी।

सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

लोकसभा चुनाव के मद्देजनर पुलिस के चुनाव सेल ने सोशल मीडिया पर नजर रखनी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा निगाह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार–प्रसार करने वालों पर रखी जा रही है। पुलिस विभाग को अंदेशा है कि कुछ लोग ग्रुप के सहारे फर्जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर फर्जी प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लोकसभा चुनावों में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के सोशल मीडिया पर एकाउंट बनाकर चुनाव प्रचार करना भी भारी पड़ सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि चुनाव सेल ने सूची बनानी भी शुरू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बहरहाल चुनाव में किसी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए बिलासपुर पुलिस तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के चलते सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। राजनीतिक दलों या फिर उनसे जुड़े नेताओं पर भद्दी और अश्लील टिप्पणी करने वालों पर पुलिस विशेष फोकस रखेगी।

आबकारी विभाग अलर्ट

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग बिलासपुर एक्शन मोड में आ गया है। जुखाला, स्वारघाट व बिलासपुर में बीते दिनों में विभाग की दो टीमों ने कार्रवाई करते हुए 65,545 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के चलते विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। सहायक आयुक्त की अगुवाई में यह टीमें रोजाना दबिश दे रही है। उन्होंने बताया कि ताजा कार्रवाई में विभाग की एक टीम जिसमें सहायक आयुक्त सतेंद्र विद्यार्थी व निरीक्षक कमल ठाकुर की टीम ने विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 38,685 रुपए का जुर्माना मजा किया है, जबिक सहायक आयुक्त अनिता कुमारी, एएसटीईओ रजनीश, चालक भुट्टो व पियून अनंत की टीम ने कार्रवाई करते हुए 26,860 रुपए का जुर्माना है। उपायुक्त जीत सिंह चौहान ने बताया कि इस जुखाला, स्वारघाट व बिलासपुर में हुई इस कार्रवाई में एक हार्डवेयर का सामान ले जाता एक ट्रक भी पकड़ा गया।

आरटीओ आफिस धर्मशाला में नहीं होगा नकद लेनदेन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जिला मुख्यालय धर्मशाला के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में अब नकद लेन–देन बिलकुल भी नहीं होगा। कार्यालय में सभी कार्य पारदर्शिता से करने के लिए नकद की बजाय ऑनलाइन लेन–देन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले नकद लेन–देन होने पर कई तरह के मामले सामने आने की शिकायतें मिलती रहती थीं, लेकिन धर्मशाला परिहवन विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था होने से भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर रोक लग सकेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धर्मशाला संजय धीमान के मुताबिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में सभी प्रकार प्रकार की फीस के नकद लेन–देन पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की फीस का लेन–देन केवल एटीएम कार्ड, डेविट कार्ड अथा क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

संदीप तलबंडी ने जीती गारली की बड़ी माली

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महादेव मंदिर गारली में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के पहलवानों ने भाग लिया। छिंज का आयोजन हर वर्ष महादेव दंगल कमेटी गारली की तरफ से करवाया जाता है। इस दंगल में इस बार दो मालियां करवाई गईं, जिसमें बड़ी माली में संदीप तलबंडी विजेता रहे तथा गुरजीत सिंह उपविजेता रहे। विजेताओं को गुर्ज व गागर और इनाम राशि देकर कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। छोटी माली में रिक्कू लखनपुर विजेता तथा बल्हसीणा उपविजेता रहे। मेले में बतौर मुख्यातिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रताप सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।

नामांकन भरने वाले उम्मीदवार के साथ सिर्फ पांच लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) डा. ऋचा वर्मा ने लोकसभा आम निर्वाचन–2019 के अंतर्गत आगामी 22 से 30 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (लीव रिजर्व) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार नामांकन भरने के लिए आने वाले उम्मीदवार के साथ निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सौ मीटर दायरे में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी और निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन हेतु उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

31 तक मांगों की नहीं हुई सुनवाई, तो हड़ताल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

बैरास्यूल पावर स्टेशन सुरंगानी के पुनर्निर्माण कार्य में जुटी कंपनियों के रोजगार मामले में अनदेखी को लेकर स्थानीय युवाओं में खासी नाराजगी है। युवाओं ने 31 मार्च तक रोजगार समेत अन्य मांगों के हल को लेकर एनएचपीसी व निजी कंपनी प्रबंधनों द्वारा कोई सुनवाई न करने की सूरत में दो अप्रैल से हडताल पर बैठ जाएंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी एनएचपीसी प्रबंधन की होगी। यह फैसला बीते दिनों बेरोजगार युवाओं की बैठक में लिया गया। इस प्रस्तावित फैसले की जानकारी जिला व पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई है। युवाओं में महिंद्र सिंह, देसराज, बलवंत, कमल ठाकुर, नरेश कुमार, खेमराज, कर्म चंद, दिनेश कुमार व विपन कुमार आदि ने बताया कि बड़े खेद का विषय है कि कंपनियों में बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मगर स्थानीय युवाओं के हितों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुददे को वे कई मर्तबा एनएचपीसी और निजी कंपनी प्रबंधनों से टेकअप भी कर चुके हैं। बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। मगर अभी तक कमेटी को भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। जिस कारण अब युवाओं ने हक पाने के लिए कडे कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत अब 31 मार्च तक कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने के चलते दो अप्रैल से हडताल आरंभ कर दी जाएगी।

खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने जिला के सभी निकायों को ठोस कचरा प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिय प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सही एकत्रीकरण, पृथक्करण व निष्पादन करना आवश्यक होता है। ठोस कचरा प्रबंधन के तहत उसकी खाद व ऊर्जा बनाना या लैंडफिल आदि गतिविधियां की जा सकती हैं। यह भी आवश्यक है कि कचरा एकत्रीकरण के बाद उसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में अलग–अलग किया जाए और क्लस्टर के स्तर पर उचित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वच्छता बेहद आवश्यक है। पहाड़ों, सार्वजनिक व अन्य स्थानों पर खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं। यदि कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा फेंकता है तो उस पर एक हजार जुर्माना तथा संस्था के ऊपर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने सभी निकायों से जिला को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने चंबा नगर तथा अन्य सभी स्थानीय निकायों से कूड़ा–कचरा पृथक्करण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी मांगी और कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा भारी मात्रा में कूड़ा जनित करने वालों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय निकायों से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी तथा कहा कि लोगों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जागरूकता लाने के लिए समय–समय पर विभिन्न कदम भी उठाए जाने चाहिएं।

अग्निकांड पीड़ितों को डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं मिली राहत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत होली के झडौता गांव में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुए अग्निकांड के पीडितों को डेढ़ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी राहत नहीं मिल पाई है। अक्तूबर 2017 में हुए अग्निकांड में दो मकान पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में तबदील हो गए थे, जबकि इस घटना में पांच परिवारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। प्रशासन की ओर से भी राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचे नुकसान का जायजा लिया था। लेकिन अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई बावजूद इसके अभी तक पीड़ितों को प्रशासन की ओर से सहायता मुहैया नहीं करवाई जा सकी है। नतीजतन परिवारों ने नायब तहसीलदार होली को एक पत्र सौंप कर राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार अक्तूबर 2017 में होली के झड़ौता गांव में दो मकान और इसके भीतर रखा गया सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया था। पीडितों में केहर सिंह, राजकुमार, विजय कुमार, अजय कुमार और रोशन लाल शामिल थे। पीडितों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का मुआवजा उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही किसी योजना के तहत गृह निर्माण के लिए भी सहायता नहीं दी गई। पीडितों का कहना है कि इस घटना में उनका सारा सामान व अन्य चीजें भी जलकर गई थी। लिहाजा पीडितों ने नायब तहसीलदार होली के दरबार में पहुंच कर उचित सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। पीडितों ने पत्र की प्रतिलिपि एसडीएम भरमौर को भी प्रेषित की है।

बिजली को तरस गए ग्रामीण, अब तक आश्वासन ही मिले

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

प्रदेश के सबसे दुर्गम एवं कठिन परिस्थितियों वाले तीन गांव शाक्टी–मरोड़ और शुगाड़ के लोग आज भी बिजली आपूर्ति की सही व्यवस्था न होने के कारण परेशानियां झेलने को मजबूर है। दरअसल इन गांवो में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस बारे में कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई लेकिन सरकारी अमले आम जन की समस्सा पर इतनी गंभीरता से गौर नहीं किया कि इसका आसानी से हल हो सके। हालात यह है कि इन गांवों के घरों में एक स्वंय सेवी संस्था की ओर से दी गई सौर लाइटों से गुजारा चल रहा है। लेकिन इस पर भी मौसम की मार भारी पड़ रही है।

हालांकि इन गांवों के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट से बिजली पहुंचाने के आश्वासन दिए गए लेकिन वो प्रोजेक्ट फाइलों में और आश्वासन में ही पूरे हुए। लोगों के घरों में फिर भी बिजली नहीं पहुंची।

जानकारी के मुताबिक तीनों गांवों में 200 से अधिक आबादी है और यह गांव सड़क से 23 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। यहां पर 40 के आसपास घर हैं। हालांकि बीच में बिजली पहुंचाने के लिए बजट का प्रावधान भी हुआ था, लेकिन फोरेस्ट क्लीयरेंस और दूसरी औपचारिकताओं के बीच मामला उलझ गया।

एक सप्ताह में नहीं बजे फोन, तो देंगे धरना

द रीव टाइम्स, ब्यूरो, कुल्लू

जनजाति लाहुल–स्पीति में गत तीन माह से ठप पड़ी दूर संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों टीडीएम कुल्लू से मिला। इस दौरान लोगों ने बीएसएनल के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि एक सप्ताह के भीतर अगर लाहुल में मौजूद बीएसएनएल के सभी टावरों को सुचारू रूप से बहाल नहीं किया गया,तो लाहुल के लोग बीएसएनएल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। लोगों ने बीएसएनल के अधिकारियों से मांग की है कि घाटी में मौजूद 11 टावरों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि लाहुल–स्पीति के दूरदराज के क्षेत्रों में भी टेलीफोन सुविधा शुरू हो पाए। लोगों ने कहा है कि अगर सात दिन के भीतर लाहुल में टेलीफोन व्यवस्था बहाल नहीं हो पाती है, तो ग्रामीण आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। जिला परिषद सदस्य जीमेद लामों का कहना है कि इस संबंध में लाहुल–स्पीति प्रशासन को कई बार लिखित तौर पर समस्या के समाधान करने का आग्रह किया गया, बावजूद इसके लाहुल घाटी में टेलीफोन व्यवस्था बहाल नहीं की गई। उन्होंने बताया कि टीडीएम कुल्लू एलडी नेगी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तीन दिनों के भीतर लाहुल के जिस्पा क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था को बाहर कर दिया जाएगा, वहीं 31 मार्च तक घाटी के अन्य क्षेत्रों में भी दूरसंचार व्यवस्था को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाहुल घाटी में बीएसएनल के 11 टावरों में से सर्दियों के दिनों में दो ही टावर चलते रहे, जबकि अन्य बंद होने से क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था ठप रही।

पीज पंचायत में कूड़ा डंपिंग साइट नामंजूर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला मुख्यालय कुल्लू के बिलकुल साथ सटी पीज पंचायत के एरिया में शहर के कूड़ा–कचरे को डंप करने के लिए प्रशासन, नगर परिषद ने साइट चिन्हित की है, लेकिन इसका विरोध जारी है। यहां डंपिंग साइट न बनाने को लेकर हाल ही में करीब साढ़े तीन सौ के करीब लोगों ने एकत्रित होकर एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि यहां पर किसी भी सूरत में कूड़ा डंपिंग साइट खुलने नहीं दी जाएगी। अगर यहां पर कूड़ा संयंत्र केंद्र खोलने की जबरदस्ती भी की गई तो पंचायत की महिलाएं चिन्हित साइट पर पहुंचकर काम राकेंगी और धरने पर बैठेंगी। हाल ही में पीज पंचायत के लोग इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर उपायुक्त से मिले हैं। अब पंचायत की 200 के करीब महिलाएं भी इसके विरोध में खड़ीं हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र उनका बरतनदार है। चिन्हित स्थान से होकर जहां आराध्य देवता जम्दग्नि ऋषि का रास्ता है। वहीं, यह जंगल पीज पंचायत के लोगों की चारागाह भी है। यही नहीं, इसके साथ स्कूल और मंदिर भी है। ऐसे में यहां पर कूड़ा डंपिंग साइट खोलना बिलकुल भी शोभा नहीं देता है। पीज पंचायत के प्रांगण में कूड़ा संयंत्र केंद्र के विरोध में हुई अहम बैठक में पंचायत सदस्यों के साथ–साथ महिला मंडल, युवक मंडल और स्थानीय लोगों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब अन्य जगह चिन्हित की गई थी तो पीज पंचायत में क्यों कूड़ा संयंत्र केंद्र खोला जा रहा है। यह शहर का सबसे नजदीक क्षेत्र है, जिसमें कूड़ा डंपिंग साइट खुलने से प्रदूषण और महामारी फैलने की आशंका भी हो सकती है। प्रशासन ने जो जगह चिन्हित की है, वहां चीड़ के लगभग 200 हरे पेड़ हैं। संयंत्र लगाने के लिए उनकी बलि चढ़ेगी। इसके अलावा पंचायत के लोगों का कहना है कि जब सरकार और प्रशासन से वाया मिंयाबेहड़ होते हुए पीज पंचायत को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था तो प्रशासन और सरकार ने फंड न होने का हवाले देते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त पंचायत के बाशिंदों ने इस पूरे क्षेत्र को नेचरपार्क और वायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के लिए भी कहा था।

बहुचर्चित हूमा देवी हत्याकांड का आरोपी दोषी करार

बहुचर्चित हूमा देवी हत्याकांड के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया है।

इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के शर्मा की विशेष अदालत ने बालीचौकी तहसील के राही गांव निवासी थलिया राम उर्फ नागू के खिलाफ भादंसं की धारा 302, 366, 364, 201 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमशरू उम्रकैद, पांच–2 साल कठोर तथा साधारण कारावास की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे छह–छह माह के अतिरिक्त कठोर और साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हूमा देवी को अगवा करने, उसकी हत्या करने, शव को एक गुफा में दबा कर साक्ष्यों को नष्ट करने और अनुसूचित जाति की होने के कारण उस पर अत्याचार करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उम्रकैद तथा उक्त जुर्माना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है।

पहले दिया शादी का झांसा

अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 जनवरी 2015 को शिकायतकर्ता मणि राम ने औट पुलिस थाना में रपट दर्ज करवाई थी कि विगत 1 जनवरी 2015 को वह बालीचौकी से शाम करीब 4 बजे घर पहुंचा तो घर में उसकी 25 वर्षीय अविवाहित बेटी हूमा देवी नहीं मिली। शिकायतकर्ता की पत्नी ने उन्हें बताया कि वह अपनी बहन के घर सैंज बरमारी गांव गई है। शिकायतकर्ता ने जब अपनी बेटी हीरा देवी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि हूमा उसके घर नहीं आई है।

इस पर शिकायतकर्ता ने अपने रिश्तेदारों के पास हूमा देवी की तलाश की लेकिन उसका कोई पता न चल सका। इसके बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी थलिया राम ने हूमा को शादी का झांसा दिया है। जिस पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

मेडल जीत लौटे तीन खिलाड़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

संयुक्त अरब अमीरात के आबूधाबी में गत दिनों संपन्न हुई अंतरराष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। इन खेलों में भारत ने 85 स्वर्ण, 154 रजत व 129 कांस्य पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया है। इन खेलों में हिमाचल के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जोगिंद्रनगर क्षेत्र के तीन खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए दो सिल्वर व कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। जगदीश चंद विशेष अध्यापक खंड चौंतड़ा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक खेलों में निशा धवन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटरु ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक व 400 रिले दौड़ में कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की और विनोद व अभिषेक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल जोगिंद्रनगर वालीबाल में रजत पदक विजेता बने। चौंतड़ा पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह, अध्यापकों, स्थानीय लोगों ने स्वागत किया।

गर्मियों की दस्तक के साथ सताने लगा डेंगू का डर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

वर्ष डैहर उपतहसील व साथ लगती पंचायतों में पहली मर्तबा 600 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ गए थे व डेंगू ग्रस्त डैहर बाजार के एक व्यापारी की मौत हुई थी। प्रसाशन व स्वास्थ्य विभाग की लाखों कोशिशों व प्रयासों के बावजूद बीमारी को फैलने से रोकने में नाकाम साबित हुए थे। गत वर्ष डेंगू की चपेट में आने के बाद पूरे क्षेत्र में बीमारी को लेकर डर व दहशत का मौहाल बना हुआ था और क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लोगों ने डैहर बाजार और घरों से बाहर निकलना तक छोड़ा दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहता था। विभाग द्वारा घर–घर चलाए गए जागरूकता अभियान के बाद डैहर में डेंगू की रोकथाम हुई थी और लोगों ने राहत की सांस ली थी। अब इस साल गर्मियों की दस्तक के साथ ही डैहरवासियों को डेंगू का डर सताने लगा है। डैहर बाजार व आसपास के क्षेत्र में फैली गंदगी व बंद पड़ी गंदी नालियां व कूड़ा–कर्कट व बेकार चीजें डेंगू मच्छरों को पनपने का मौका प्रदान कर रहे हैं। हालांकि गत वर्ष बीमारी के फैलने के बाद प्रसाशन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में स्वास्थ्य टीमों द्वारा घर–घर गांव–गांव जाकर डेंगू मच्छरों के लारवा को खत्म करने व लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया था और डेंगू ग्रस्त मरीजों की पुष्टि हेतु डैहर सीएचसी में मरीजो के खून के सैंपल लेकर मंडी अस्पताल की लैब में जांच करवाने व क्षेत्र के लोगों को विभाग द्वारा ऑडोमॉस क्रीम भी निःशुल्क बांटी गई थी और क्षेत्र में फागिंग मशीन से प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग करवाई गई थी।

धारा 370 आईपीसी – मानव तस्करी – दास के रुप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना।

जो भी कोई, धमकियों का या बल का या किसी अन्य प्रकार के दबाव का उपयोग कर, या अपहरण करके, या धोखाधड़ी, या शक्ति का दुरुपयोग करके, या प्रलोभन द्वारा, भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित, शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहित, आश्रयीत, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति हासिल करने के लिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का, भर्ती करना, ढोना, शरण देना, स्थानान्तरण, या प्राप्त करना कारित करता है, वह तस्करी के अपराध का काम करता है।

जो भी कोई तस्करी के अपराध का काम करता है, तो उसे कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति नाबालिग की तस्करी के अपराध में एक से अधिक बार दोषी करार हुआ है, तो उसे आजीवन कारावास जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

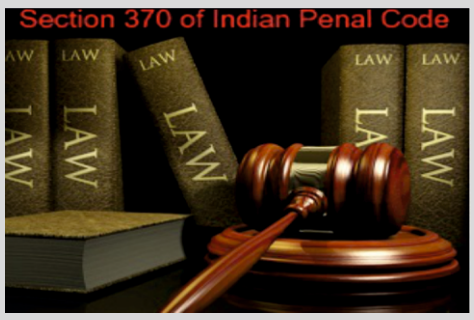

लागू अपराध व सजा

1. व्यक्ति – व्यक्तियों की तस्करी।

सजा–सात से दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

2. एक से अधिक व्यक्ति–व्यक्तियों की तस्करी।

सजा – दस वर्ष से आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

3. नाबालिग व्यक्ति/व्यक्तियों की तस्करी।

सजा – दस वर्ष से आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

4. एक से अधिक नाबालिग व्यक्ति/व्यक्तियों की तस्करी।

सजा – चौदह वर्ष से आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

5. नाबालिग की तस्करी के अपराध में एक से अधिक बार दोषी।

सजा – आजीवन जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

6. यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की तस्करी में शामिल है

सजा – आजीवन जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

क्या है टीबी? जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

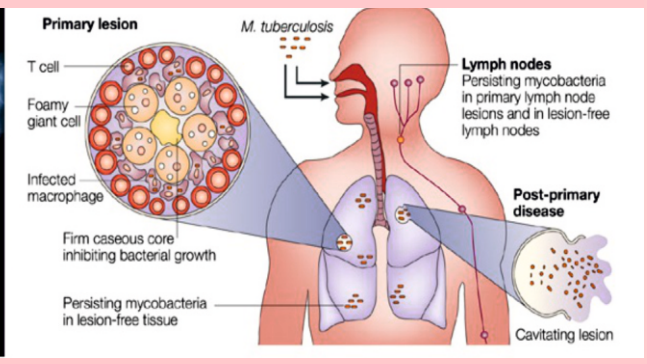

द रीव टाइम्स ब्यूरो

टी.बी. जिसे हिंदी में क्षय रोग और मेडिकल भाषा में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं एक बैक्टीरिया जनित रोग है। यह एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा उत्पन्न संक्रमण है। यह बैक्टीरिया शरीर के सभी अंगों में प्रवेश कर जाता है। हालांकि ये ज्यादातर फेफड़ों में ही पाया जाता है। मगर इसके अलावा आंतों, मस्तिष्क, हड्डियों, जोड़ों, गुर्दे, त्वचा तथा हृदय भी टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। क्षयरोग को कई नामों से जाना जाता है जैसे टी.बी. तपेदिक, ट्यूबरकुलासिस, राजयक्ष्मा, दण्डाणु इत्यादि नामों से जाना जाता है।

टीबी के प्रकार

1. फुफ्सीय टीबी– फुफ्सीय क्षय रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो लगता है लेकिन हर व्यक्ति और फुफ्सीय टी.बी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग–अलग पाएं जाते हैं। इसमें कुछ सामान्य लक्षण जैसे सांस तेज चलना, सिरदर्द होना या नाड़ी तेज चलना इत्यादि समस्याएं होने लगती हैं।

2. पेट का टीबी– दरअसल पेट के टी.बी के दौरान मरीज को सामान्य रूप से होने वाली पेट की समस्याएं ही होती हैं जैसे बार–बार दस्त लगना, पेट में दर्द होना इत्यादि। जब तक पेट के टी.बी के बारे में पता चलता है तब तक पेट में गांठें पड़ चुकी होती हैं।

3. हड्डी का टीबी– हड्डी में होने वाले क्षय रोग के कारण हड्डियों में घाव पड़ जाते हैं जो कि इलाज के बाद भी आराम से ठीक नहीं होते। शरीर में जगह–जगह फोड़े–फुंसियां होना भी हड्डी क्षय रोग का लक्षण हैं।

टीबी के लक्षण–

1. खांसी (दो सप्ताह या उससे ज्यादा दिन तक)
2. खांसी के दौरान मुंह से खून आना
3. भूख कम लगना और वजन का कम होना
4. ठंड लग कर पसीने के साथ बुखार आना
5. कई लोगों में शरीर में गांठे भी देखने को मिलती हैं

बचाव

1. आप बीसीजी का टीका लगवाकर टीबी से बच सकते हैं।
2. अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति को टीबी है तो जितना हो सके उससे दूरी बना कर रखें। क्योंकि ये एक तरह का संक्रमित रोग है।
3. टीबी के मरीज को मास्क पहनकर रखना चाहिए। ताकि सामने वाले का आपके छींकने या फिर खांसने से रोग न फैलें।
4. मरीज को जगह जगह नहीं बल्कि किसी एक पॉलिथीन में थूकना चाहिए।
5. मरीज को पब्लिक चीजों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ताकि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसकी चपेट में न आए।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

अपने दिमाग को तेज कैसे बनाएं?

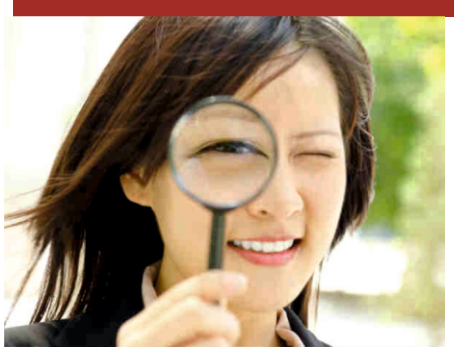

आप अपने शरीर को फिट और एक्टिव रखने के लिए व्यायाम करते है लेकिन अपने मन को स्वस्थ और दिमाग को तेज बनाएं रखने के लिए क्या करते है ? किसी पहेली को सुलझाना या अपने नए गैजेट को पूरा छान मारना और उसके हर फीचर्स को जान लेना आपके दिमाग को शार्प बनाता है लेकिन शायद काम पर्याप्त नहीं है। हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने दिमाग को शार्प बना सकते है। कई बार बढ़ती उम्र के कारण या उत्तेजना की कमी के कारण मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करता है और हम चीजों को भूल जाते है या ज्यादा समय तक ध्यान नहीं रखते। बताएं जाने वाले सभी काम मजेदार है और इन्हे आपको हर दिन की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके बाद खुद में आए परिवर्तनों को देख लें।

हर बात को सही तरीके से समझने की कोशिश करें एक सप्ताह के लिए किसी एक वस्तु या व्यक्ति को समझने के लिए अपना टारगेट बना लें। आप ऐसा यात्रा के दौरान या मेट्रो में या फिर चाय – कॉफी ब्रेक के दौरान भी कर सकते है। ऐसा करते समय आप चाहें तो अपने साथ एक नोटपैड रखे, जिसमें उस व्यक्ति की इमेज को ड्रा करें या उसकी छोटी – छोटी हरकतों व अदाओं को नोट करें। इस एक्टिविटी को करने से आपकी शॉर्ट – टर्म मेमोरी बढ़ेगी । सप्ताह के अंत में या संडे की शाम को आप उन सभी ऑब्जेक्ट को बिना देखे याद करने की कोशिश करें । अगर आप सभी लोगों को याद कर लेते हैं तो आपकी लांग टर्म मेमोरी काफी अच्छी है और अगर नहीं कर पाते हैं तो मेहनत करिए, कुछ समय बाद सारे ड्रा किए चित्रों को आप आसानी से रिकॉल कर लेंगे।

ध्यान से सुनें जब आप फोन कॉल रिसीव करें, तो मोबाइल स्क्रीन पर बिना नाम देखे, उस व्यक्ति की आवाज से उसे पहचानने की कोशिश करें या फिर जब आप गाना सुन रहे हों तो उस गाने में इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत उपकरणों को पहचानने की कोशिश करें। इसके अलावा, उसके सिंगर की आवाज भी पहचानने की कोशिश करें। एक सप्ताह तक हर दिन एक गाने को सुनें। इससे आपकी याददाश्त में तेजी आएगी।

किसी भी वस्तु का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना

अगर आप किसी भी वस्तु का निर्माण करने की क्षमता का विकास कर लेते हैं तो आप छोटी – छोटी चीजों से कुछ बनाने की दक्षता हासिल कर लेते हैं। इसके लिए आप दो तरह की एक्सरसाइज कर सकते है : जिगशॉ पजल लें और उसे कई टुकड़ों में न बांटकर जैसी मिले वैसी ही रहने दें और फिर ध्यान से देखें कि आप इन्हे कैसे अरेंज कर सकती हैं। एक सप्ताह बाद इसे फिर करें और थोड़े समय बाद पजल को कठिन करते जाएं, उसके टुकड़ों की संख्या बढाते जाएं। जब आप बोर हो जाएं तो कोई और जिगशॉ ले लें।

शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करें,

क्रिएटिव भाषा बोलें कई बार हम सही शब्द को लिखने या बोलने में इस्तेमाल करते है जो काफी फॉमर्ल होता है, लेकिन वह शब्द हमारी लांग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जगह बना चुके होते है। ऐसे ही शब्दों से आप अपने दिमाग को तेज बना सकते है। आप दिन में न्यूज देखते या पढ़ते ही होंगे, उनमें प्रयोग होने वाले शब्दों व हेडलाइन को ध्यान से सुबह पढ़े और शाम को नोटबुक पर लिखकर देंखे। नए शब्दों पर ज्यादा ध्यान दें और भाषा की क्रिएटिविटी पर भी फोकस करें। साथ ही चाहें तो पर्सनल ब्लॉग बना लें।

साभार : ऑन लाइन

Towards Accountability of Parliamentarians

During the election process the contestants keep on occupied in counting of probable votes and devising all kind of strategies which help in visualizing heavier weight. The contestants are hardly on the line of in-visioning development of their constituency. In normal course, a member of parliament is supposed to deliver on two fronts; first contributing in development of the constituency and second contributing in nation building through deliberations in the parliament. Having given highest status in the Indian democracy to legislate various aspects, unfortunately, there is no formal selection process based on competency mapping. Unlike the bureaucrats who undergo rigorous selection and training process after obtaining minimum eligibility qualifications; the people going to rule the country are exempted from everything. Anyone can win elections based on influence irrespective of education background and proven track record. There are three pillars of democracy i.e. Legislative, Executive judiciary. The selection process of the later two is more systematic and outcome oriented. Whereas the same for electing people to exercise the highest powers is left on the biggest selection panel comprising all adults i.e. voters. And the results have been before us for the last seventy years. The constitutional arrangement proves to be ill democratic for the following reasons.

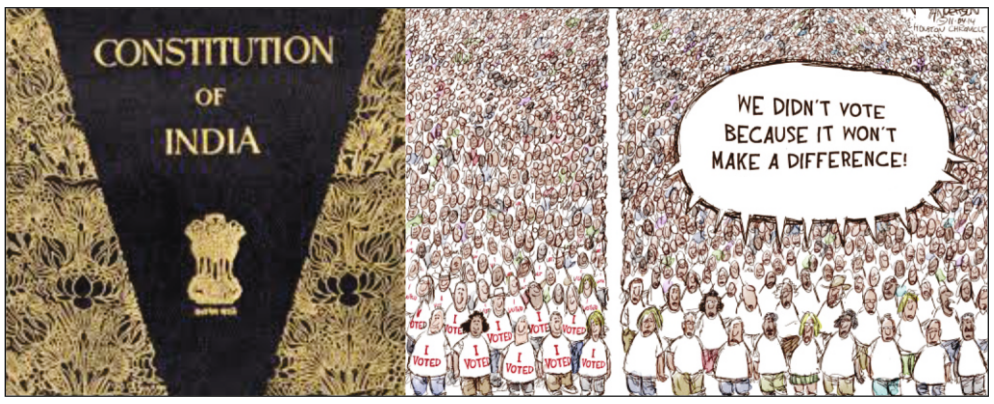

First of all, it gives right to elect anyone of one's choice s.e. means ultimate authority which is always dangerous. No one should be vested with the ultimate authority which creates many voices.

Secondly, it does not have provision to amend the mistake if the selection proves to be wrong. A citizen is bound to live with their committed mistakes until next elections. Whereas there could have the provision of Right to Recall if the candidate does not prove to be worth.

Thirdly, there is no prescribed way of identifying capabilities, intentions and dynamism of the candidates before mass polling. Hence, vacuum of short listing process.

Fourth lies at the level of public-people who simply take the agenda of the political parties for granted. There is no culture of asking every contestant to come up with the respective developmental and political vision.

Fifth again lies at the end of the public, who does not ask for the outcome of the past tenure in case of repeating candidate. Many of the MPs do not even spend the M P led fund and the question of mobilizing additional funds remains far away. We can at least, publically know from the candidates about their vision, likely priorities and commitments before the election date is near. This may gradually help inculcating the sense of accountability and expected dynamism amongst the prospective parliamentarians.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

CHASING DOWN 370 IN WORLD CUP

More than a call for self-determination or resolving territory dispute, Kashmir issue is an ideological and psychological warfare. I can agree with Arnab Goswami on anything but his stand on cricket with Pakistan in 2019 World Cup. How can we refuse to play a league match in world cup with Pakistan? Do we have other ways to show solidarity for Pulwama martyrs of CRPF? India not playing will only help Pakistan secure two valuable points with fair chances for them to qualify to play quarterfinals. Will we love Pakistan get benefitted by our foolishness? Who can possibly allow India not taking on and beating Pakistan in world cup? Tukde-tukde gang, Pakistan Team, terrorists, Kashmiri separatists, Pakistan sympathisers in India and above all Imran Khan for sure will hate to take on a mighty side like India. Imran Khan can be greatest political fool but has a very smart cricketing brain. With their worst team imaginably ever, Pakistanis are having worst nightmares taking on arguably the world's best side, India. Not playing a match against Pakistan will only be India's playing for Pakistan. Anger spoils reasoning and extreme anger spoils it absolutely.

Ofcourse Indian players will be under tremendous pressure taking on Pakistan , especially after recent developments in our relations with one time most favoured nation. But this is time we test those who we elevate to images of superheroes. Indian team will be under pressure, no doubt; despite our being one of the mightiest sides of world, India should not giveaway an opportunity to archrivals saving them count those unbearable long hours of sleepless nights. With this, Indian cricket side not playing Pakistan will be as if Mike Tyson is denied an opportunity knock college champion out or Brazil denied kick teams like Nepal or Myanmar out of FIFA world cup. India plays cricket as a game with any other team but Indo-Pak cricket is nothing less than a war separating two sides by 22 yards' LOC.

Cricket match neither cause any collateral damage nor win territories but of course help register a psychological edge and advantage over rival nation. Again this is ironical that ever since Indian cricket team started dominating world cricket, India banned all bilateral cricket series with Pakistan. On the contrary last few decades would have been an ideal time to better our records against Pakistan.

Now let us reverse the scenario and considering we do not play against Pakistan, they will be benefitted not only in earning those two valuable points but who knows India with one minor upset in league matches fail to make it for second round? Let us take it further and imagine a situation where both, India and Pakistan make it for next levels and have to play in semis or finals against each other. Can we say 'no' if that be a knock out? Will we play against Pakistan in finals or giveaway World Cup without contesting? Considering all this, not taking on Pakistan appears just to be an ironical and insane idea. Yes, there can be thousand other ways to isolate Pakistan globally, be that diplomatic or military action but not playing cricket is madness without method.

Ideally, India should have put enough pressure on ICC to expel Pakistan from participating international cricket in all formats. Why can India not stay out of tournament and bycott cricket completely, say; for few years? ICC generates roughly 80% of its revenue from BCCI and they, along with sports channels can ill-afford ignore a cricket crazy nation like India comprising 100 million or more audience. BCCI will definitely detest all this boycott and banning cricket. They are money making machines and hardly care about country. Gamblers must be put under scanner now and they must know how to behave in situations like these. Yet the fact is, we have failed to figure out all these possibilities in advance or have voluntarily ignored and sacrificed nationalism for cricket.

Not playing a match at early stage of tournament is nothing more than a sub-continental widow wail. Either boycott completely or let our cricket heroes deliver more than their best if any other superlative could manifest the anticipations of Indians. Cricketers make huge fortunes particularly in india by playing and enjoy living luxurious lives get very rarely in situations where they could feel the horror of ordinary life of an ordinary man by just losing a cricket match. The feeling and fear of losing a league match against Pakistan must be more humiliating and suffocating than being beaten by Afghanistan or Zimbabwe in the world cup finals. Apparently same applies for Pakistani team, though will be under less stress for their being a weaker side but momentarily a miracle will be expected by Pakistanis before TV sets are broken in wrath. But real test of nerves will be moment flight lands at Pakistani airport once tournament is over, which is why India must make Pakistan team most uncomfortable entering Islamabad or Karachi having extremists and radical natives for their welcome will be fitting tribute by Indian cricket team to hundreds and thousands of sacrifices by our defence forces.

Not playing just for registering a protest against Pakistan in world cup will only damage us since no other country can experience the anger or anguish we have been subjected to. I take this for an opportunity to completely decimate Pak team irrecoverably. Recent reactions from IOC already started to reflect that we may isolate ourselves more than we succeed in cornering Pakistan globally. We must foresee and take account of every possible reaction by world community and avoid a knee jerk action which could boomerang to our disadvantage.

Days for cricket diplomacy and 'aman kee asha' no doubt are over. For corporates like BCCI, national interest can never be a priority over money. Cricket can be used as a handy tool by India for its dominance in ICC and in order to exploit this advantage in our favour, government of India first of all must take over BCCI so that fitting decisions are taken in national interest once situation arises. But that can be achieved only if India raises the cost for its availability. World cricket can not survive without India and let ICC make a choice between India and Pakistan. Boycotting a match or two will yield nothing so we must act prudently next time and make world community force terror sponsor country out of cricket world.

Kamlesh Sharma, Shimla (HP)
(Guest Writer) 9817540956

ये जो पब्लिक है ये सब जानती है...

सत्ता मोह ने सारी मर्यादाओं को दरकिनार किया है / हिमाचल भी अछूता नहीं... सत्ता के लिए सब जायज़

राजनीति आज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है उसका वर्णन और विवरण शब्दों के स्वर–व्यंजन से बाहर है। राजनीति यदि हमारे देश के भविष्य को तय करती है तो क्या आम आदमी को ये हक़ नहीं है कि वो राजनीति का भविष्य तय करें ? संविधान हमें स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है लेकिन उसकी भी एक सीमा है, एक दायरा है। मूल स्वतंत्रता अपने आप में एक वृहद परिभाषा को समाहित करता है। किंतु 1947 के पश्चात् वर्तमान तक एक परिपक्कव राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हमारा देश छिछोरी और स्वार्थपरक राजनीति के कुचक्र में फंसता चला जा रहा है। सेवा भाव और देश के कुशल संचालन के लिए जिस राजनीति की परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बुद्धिमान रणनीतिकारों ने की थी, उसका वर्तमान स्वरुप इतना विभत्स होगा..कल्पना से बाहर है। सत्ता की भूख और देश के भाग्यविधाता मतदाओं के अरमानों को कुचलने के लिए सत्ता लोलुप किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

देश में चुनावों का दौर इस बात को तसदीक करता है कि अब वो सब सुनने और देखने को मिलेगा जो कुछ विगत पांच वर्षों में छूट गया होगा। कुर्सी का खेल इतना अजब है कि सिद्धांतों और मर्यादाओं को तो छोड़िए, अपने सगे और बंधुओं को भी यदि बलि चढ़ाना पड़े तो गुरेज़ नहीं करते हैं। देश के हर राज्य में सत्ता के लिए मुद्दों का अभाव है और व्यक्तिगत एवं अमर्यादित टिप्पणियों एवं आलोचनाओं की भरमार है। इस पर टीवी चैनलों ने आग में घी का काम किया है।

हिमाचल प्रदेश राजनैतिक और सामाजिक समदृष्टि में एक शांत प्रदेश की छवि को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर हिमाचल प्रदेश की पहचान एक ईमानदार प्रदेश के रुप में जानी जाती है। परन्तु देश में बह रही मटमैले जल के राजनीतिक नालों के छींटे अब हिमाचल पर भी पड़ रहे हैं। यहां विधानसभा के वैसे तो 68 सदस्यों की बारात ही है और देश के संचालन के लिए लोकसभा के 4 ही सदस्य चुन कर दिल्ली पहुंचते हैं....किंतु ये 68 सीटें और 4 लोकसभा की सीटें कभी–कभी तो राजनीति की परिभाषा ही बदल देती है । 2019 के लिए लोकसभा का चुनावी शंखनाद होते हैं देश

भर में इस महासमर के लिए शानदार आगाज़ हो गया है । हालांकि हिमाचल में आख़िरी चरण में चुनाव होने हैं लेकिन इसकी बिसात बिछनी शुरु हो चुकी है ।

हिमाचल की राजनीति में एक पुराना और बड़ा नाम पंडित सुखराम का है। वैसे इनकी राजनीति की बिसात का मैदान तो मंडी है लेकिन हिमाचल में इनकी राजनीति देश में मंत्री पद पर रहते हुए दूरसंचार की क्रान्ति के लिए जानी जाती है। इसी दौरान राजनीतिक चालों में मोहरों की बिसात ऐसी बिछी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके ताल्लुक़ात में खट्टास आती गई और एक समय पर तो पूरा प्रदेश और देश स्तब्ध रह गया जब पंडित सुखराम के घर में सीबीआई की रेड़ पड़ी जिसके बाद काफी कुछ बदल गया। बैग और सूटकेस के अलावा तकिए के नीचे से लगभग 4 करोड़ के आसपास नगदी पकड़े जाने पर उन्हें जेल तक की यात्रा करनी पड़ी। बाद में पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन कर हिमाचल की राजनीति में मात्र कुछ सीट ही लेकर भी पासा पलट दिया।

पहले कांग्रेस, फिर हिंविका, फिर बीजेपी और अब फिर से कांग्रेस का दामन ..... क्या ये सारी उठापठक जन सेवा में हो रही है अथवा प्रदेश की जनता का उपहास किया जा रहा है। पंडित सुखराम ने परिवार सहित भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थामा क्योंकि बेटे अनिल शर्मा को विधायक और मंत्री बनाने की तीव्र लालसा मन में थी। हुआ भी ऐसा ही.... अनिल शर्मा मंडी से विजयी हुए और बीजेपी की सरकार बनने पर मंत्री भी बन गए। उसके बाद लोकसभा के चुनावों का बिगुल क्या बजा....सबसे अधिक हैरान करने वाला निर्णय पंडित सुखराम और उनके परिवार का ही सामने आया। मंडी लोकसभा सीट से सुखराम के दूसरे पोते आश्रय कि ज़िदद कह लो या दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पर दबाव की राजनीति होने लगी। दबाव इस बात का कि मंडी सीट भी सुखराम के परिवार के पास ही हो और मंत्री अनिल शर्मा के पुत्र आश्रय वहां से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें। इस पर बीजेपी की हरि झंडी न मिलने के बाद सुखराम परिवार ने पैंतरा मारा और दिल्ली में कांग्रेस का दामन पुनः थाम कर आश्रय के लिए मंडी से टिकट भी झटक लिया। कांग्रेस की इसके पीछे भी रणनीति है तो बीजेपी के लिए अब संकट का समय है क्योंकि बेटा आश्रय यदि मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार है तो पिता अनिल शर्मा बीजेपी सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं। उनकी मजबूरी ये है कि वो किसी के लिए भी प्रचार नहीं कर पाऐंगे क्योंकि उनके सामने धर्मसंकट आ गया है।

क्या राजनीति अब इन्हीं परिवारों और तामझाम के साथ सिमट कर कुछ ही लोगों के हाथ रह गई है। क्या सारी शक्तियों एवं सत्ता की चाबी कुछ ही लोगों और परिवार के पास संदूकबंद रहेगी , क्या आम कार्यकर्ता या समाजसेवियों को कभी भी अवसर के नाम पर न्याय नहीं मिलेगा ? ऐसे कुछ प्रश्न पढ़ी लिखी जनता करती तो हैं परन्तु विकल्प के नाम ठगी सी रह जाती है। खुद को साबित कर जन प्रतिनिधित्व के लिए नेतृत्व करना एक अलग बात है.... अपने पुरखों की पहुंच और रुतबे को सीढ़ी बनाकर सत्ता के आसमान में छलांग लगाने की प्रवृति तो इस देश के कोने–कोने में कैंसर की तरह फैल गई है। इसी का निर्वहन सुखराम के परिवार ने भी किया है।

उधर वीरभद्र सिंह ने एक बार 'आया राम गया राम' का संबोधन कर सुखराम पर ज़बरदस्त राजनैतिक प्रहार किया था और जब–जब अवसर मिला यह प्रतिद्वंद्वता जगज़ाहिर होती भी रही। किंतु सुखराम के पाला बदलने में पीएचडी को देखते हुए यह कहना ग़लत न होगा कि मौकापरस्त राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है। मंडी में सुखराम प्रभाव को देखते हुए पार्टियां भी समय–समय पर पैंतरेबाजी करती रही है।

यहां संभावनाओं को निचोड़ता प्रश्न यह भी है कि क्या आम कार्यकर्ता कभी टिकट की दौड़ में शामिल नहीं हो पाएगा। सत्ता पर एक परिवार और कुनबों का आधिपत्य लोकतंत्र का उपहास ही कहा जाना चाहिए। धन, बल से टिकटों की खरीदफरोख़्त और मौकापरस्ती से सत्तासीन होकर क्या हम स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की मूल परिभाषा को परिभाषित कर पाने में सफल हो पाऐंगे ? क्या क़ाबिलियत इन्हीं चंद परिवारों की जागीर बन कर रह गई है ? क्या आम इंसान जो ग़ैर राजनीतिक पृष्टभूमि से संबद्ध है और इन तथाकथित राजनेता ठेकेदारों से कहीं अधिक अनुभवी और पढ़े–लिखे हैं...ये इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते ? क्या आम कार्यकर्ताओं को आटे की लेटी सना कनस्तर उठाने, पोस्टर चिपकाने, झंडा–डंडा लेकर ज़िंदाबाद करने तक ही सीमित किया जाता रहेगा ? ये कुछ प्रश्न कंटीले ज़रुर हैं लेकिन इनका उत्तर ढूंढे बिना मतदान का यह महासमर अधूरा ही रह जाऐगा। पिंजरे के भीतर का पंछी श्वास तो ले सकता है परन्तु वह आज़ाद है.....यह कहना सर्वथा अनुचित है।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

ए–सैट...फलक पर भी हिंदुस्तानी बादशाहत

अंजना ठाकुर

वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण कर भारत ने साबित कर दिया था कि धरातल पर महाशक्ति बनने से उससे कोई नहीं रोक सकता। अब 21 साल बाद 27 मार्च 2019 में ए–सैट के सफल परीक्षण से इस बात की भी तस्दीक हो गई कि धरातल से फलक तक भारत का सिक्का चलता है। ये वो पल है जब भारत ने एंटी सेटेलाइट मिसाइल को 3 मिनट में जमीन से 300 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में पहुंचाया और तय लक्ष्य को भेद कर हम हिंदुस्तानी अंतरिक्ष की भी महाशक्ति बन गए।

यानि जल–थल और नभ, अब तीनों में भारत की सुरक्षा को भेदना मुश्किल नहीं बल्कि नामुकिन है। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसी महाशक्तियों ने ये उपलब्धि काफी पहले हासिल कर भारत को कमजोर समझने की जो काल्पिनक रेखा अपने जहन में खींची थी, ए–सैट ने उस रेखा को धुंधला नहीं किया बल्कि स्टीक लक्ष्य साध कर उस काल्पनिक रेखा का अस्तित्व ही मिटा दिया। भारत की इस उपलब्धि पर अंतरिक्ष संधि की अवहेलना, अंतरिक्ष साझा विरासत है जैसे तंज कसना उन देशों की खीज को स्पष्ट करते हैं जो भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को इरादा भारत नहीं रखता। स्पष्ट है कि भारत की सुरक्षा को भेदना अब आसान नहीं है। समर्थकों के लिए मोदी सरकार की यह एक और उपलब्धि है तो विपक्ष के लिए चुनावी स्टंट। लेकिन बुद्धिजीवियों के लिए यह भारत की विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि है जो आने वाली पीढ़ियों को दुनिया के सामने और अधिक मजबूती से खड़ा होने में मदद करेगी।

अंतरिक्ष में भारत की सफलता का सफर 56 साल पहले केरल के तिरूवनंतपुरम में थुंबा से 21 नवंबर 1963 से शुरू हुआ था। यही वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अंतरिक्ष में पहला रॉकेट लॉच किया। अमेरिका 1958 में वह उपलब्धि कर चुका था जिसे हमने रॉकेट लॉच करने 56 साल बाद प्राप्त किया। अमेरिका ने 1958 में, पूर्व सोवियत संघ ने 1964 में तो चीन ने 2007 में यह उपलब्धि हासिल कर आकाश में अपनी बादशाहत पर इतराना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब भारत को चुनौति भी दी और मजाक भी उड़ाया। भारत ने अप्रैल 2012 में अग्नि–5 के सफल परीक्षण के समय ए–सैट को लेकर अपनी मंशा साफ की थी। खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका और उसी सरीखे दूसरे कुछ देशों ने उस समय भारत की इस

मंशा को कपोल कल्पित समझा और इसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन अगले सात साल के भीतर ही भारत ने सबका मुंह बंद दिया। हालांकि अगर हमारे नीति नियंताओं की राजनैतिक रीढ़ मजबूत रही होती तो सात का अंतराल कहीं कम होता और हिंदुस्तान पूरे विश्व को चार साल पहले यानि 2015 में ही अपनी आकाशीय ताकत दिखा देता।

बहरहाल, भारत का मिशन शक्ति स्टीक लक्ष्य भेद कर ऐतिहासिक उपलब्धियों की फेहरिस्त में अंकित हो गया। यह सबसे बड़ा और सुखद सत्य है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत अंतरिक्ष में युद्ध करने में न केवल सक्षम हुआ है बल्कि यूं कहा जाए कि दक्ष हो गया है तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

दरअसल इनसान जहां भी जिस भी क्षेत्र में भी विकास करता है वहां उतनी ही अधिक चुनौतियां भी मिलती है और युद्ध की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती है। जब भारत ने 56 साल पहले रॉकेट लॉच कर अंतरिक्ष का सफर शुरू किया था तभी चुनौतियां भी स्वीकार कर ली थी । इसी का नतीजा है कि आज भारत अंतरिक्ष में युद्ध करने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। पड़ोसी मुल्कों से तनाव के बीच इस उपलब्धि का मायने और भी बड़े और गहरे हो जाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मिशन शक्ति को दुनिया के सामने रखा उससे उन्होंने एक ए सैट से कहीं निशाने साधे, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले उन्होंने 27 मार्च को ट्वीट किया, मैं 11.45 से 12 बजे के बीच महत्वपूर्ण संदेश के साथ देश को संबोधित करूंगा। चुनावी दौर में भारत क्या किसी भी देश में इस तरह के ट्वीट से शोर मचना लाज़मी था। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तक भी ट्वीट पहुंचा, उसके जहन में तरह तरह की कल्पनाएं गोते खाने लगी, किसी ने कहा बालाकोट के बाद एक और सर्जीकल स्ट्राइक या पाकिस्तान पर आक्रमण, बड़े आंतकवादी की गिरफ्तारी तो कुछ ने सोशल मीडिया पर व्यक्त विचारों से देश में इमरजेंसी तक की कल्पना कर ली। कई नेताओं ने ट्वीट पर ट्वीट किया– चुनावों का परिणाम घोषित करेंगे मोदी।

बहरहाल, 27 मार्च बुधवार सुबह 11.16 मिनट पर जो घटित हुआ वह इन सभी कल्पनाओं से परे था जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनियां की सांसे कुछ पल के लिए थाम ली। तीन मिनट में आकाश तक 300 किलोमीटर का रास्ता तय कर भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया और तथाकथित महाशक्तियां दांतो तले अंगुलियां चबाती रही। ऐसे देश जो पहले खुद आकाश में लड़ने के लिए हथियारों को संजो चुके हैं वह भारत की उपलब्धि पर नसीहत देते नजर आए। इन सब के बीच भारत के लिए यह पल गौरवान्वित करने वाला था। मिशन शक्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश टीवी, रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि भारत ने एक एंटी–सैटेलाइट हथियार के जरिए धरती से करीब एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जो किया है, वह भारत के वैज्ञानिक, सामरिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य शांति बरकरार रखना है, युद्ध का माहौल बनाना नहीं. ।हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का मकसद शांति, भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति है. उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के तहत । सेट मिसाइल ने 3 मिनट में लाइव सेटेलाईट को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का यह मिशन शक्ति भारत के सपनों को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम है। रक्षा विशषज्ञों के मुताबिक यह मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस मिशन के तहत भारत जल और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकता है। अर्थात् अगर कोई दुश्मन देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रख रहा है या फिर जासूसी कर रहा है तो भारत उसकी मिसाइल को नष्ट कर सकता है।

सही मायानों में यही है, 'नया भारत'।

अंजना ठाकुर, सहायक संपादक
anjna@iirdshimla.org

मुंह से शराब की गंध आना जमानत याचिका रद्द करने का आधार नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मात्र आरोपी के मुंह से निकलने वाली शराब की गंध उसकी जमानत याचिका को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि सत्र न्यायाधीश ने किस प्रावधान व कानून के तहत प्रार्थी की याचिका को रद्द कर दिया। अगर जमानत याचिका को रद्द ही करना था तो इसे केवल कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ही रद्द किया जा सकता था।

हाईकोर्ट ने साथ ही सत्र न्यायाधीश चंबा को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा है कि उन्होंने किस प्रावधान के तहत प्रार्थी की जमानत को रद्द कर दिया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार जब मामला गवाही के लिए सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत की समक्ष लगा था तो सत्र न्यायाधीश ने पाया कि प्रार्थी के मुंह से शराब की गंध आ रही है।

दिव्यांगजन बिना प्रतीक्षा कर सकेंगे मतदान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान दिव्यांगजनों को प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही वह मतदान कर सकेंगे। इस संबंध में निर्वाचन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दिव्यांगज किसी भी तरह की सहायता के लिए बूथ स्तर के अधिकारी से सहायता के लिए संपर्क कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार बताया कि ब्रेल बैलेट गाइड और एडजेस्टेबल ब्रेल युक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत दृष्टिबाधित, अस्वस्थ मतदाता को सहायक साथ लाने की अनुमति के बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। दिव्यांगजनों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों को सूचक, हेल्प डेस्क, धरातल पर मतदान केंद्र, प्रवेश द्वार से लेकर मतदान कंपार्टमेंट तक बिना किसी बाधा के खुला मार्ग, रैंप, सुलभ शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, बूथ स्वयंसेवक तथा मतदान से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर सुविधा के लिए व्हील चेयर की ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से बुकिंग मतदान के दिन से पहले की जा सकती है।

राजधानी में पैर पसारने लगा पीलिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी शिमला में पीलिया पैर पैसार रहा है। आइजीएमसी व डीडीयू अस्पताल में रोजाना चार से पांच केस पीलिया के आ रहे हैं। ये मामले अधिकतर शिमला शहर के विकास नगर, पंथाघाटी, मल्याणा, संजौली, समरहिल समेत भराड़ी इलाके से आ रहे हैं। मंगलवार को डीडीयू में दो मामले और आइजीएमसी में तीन मामले पीलिया के आए। जांच करने पर मरीजों में हेपेटाइटिस–ई टाइप का पीलिया पाया गया। हेपेटाइटिस–ई दूषित पानी से फैलता है।

एच.आई.वी. रोकथाम पर अंतर–विभागीय बैठक आयोजित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी ने एच.आई.वीध्एड्स की रोकथाम के लिए शिमला में एक अंतर–विभागीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी के अध्यक्ष आर.डी. धीमान ने की। इस बैठक में एच.आई.वी. से सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक घटकों पर विचार किया गया।

सभी सम्बन्धित विभागों तथा संगठनों की इस बैठक में एच.आई.वी. होने के खतरे को कम करने तथा इससे पीड़ित व प्रभावित लोगों पर इसके प्रभाव में कमी लाने को मिली बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया पर विचार किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने अपने सम्बोधन में कहा कि विभिन्न विभाग एड्स पर नियंत्रण तथा रोकथाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है, जिससे देश में वर्ष 2030 तक एड्स उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

वेतन व पेंशन के लिए 500 करोड़ कर्ज लेगी सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र नौ दिन शेष हैं। लेकिन हिमाचल की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सरकार 500 करोड़ रुपये कर्ज लेने जा रही है। कर्ज़ इसलिए लिया जा रहा है ताकि कर्मचारियों व पेशनभोगियों को वेतन व पेंशन का भुगतान किया जा सके

सरकार को विकास कार्यों की देनदारियों का भुगतान भी करना है। इस कारण कर्ज लेने की तैयारी है। प्रदेश का कर्ज का आंकड़ा 50 हजार करोड़ रुपये को पार कर चुका है। चालू वित्त वर्ष में इसी महीने 500 करोड़ रुपये कर्ज लिया जा सकता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति की हालत यह है कि सरकार एक महीने के भीतर फिर कर्ज लेने के लिए बाध्य हुई है। इससे पहले सरकार ने 800 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। महज तीस दिनों के भीतर ही सरकार 1300 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर हुई है। कर्ज लेने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं

हुड़दंगियों ने रिज पर पीटा पुलिस कर्मी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

होली के दिन रिज मैदान पर कुछ लोगों ने पुलिस कर्मी की बुरी तरह पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि आरोपित सैनिक हैं, जिन्हें पुलिस ने नामजद कर दिया है। हालांकि पुलिस आरोपितों के नाम बताने से पल्ला झाड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों में समझौता करवाने की तैयारी है। पुलिस इस मामले का ज्यादा तूल नहीं देने के पक्ष में है। सेना से मामला जुड़ा होने कारण आला अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। वीरवार को दोपहर करीब साढ़े 11 बजे कुछ लोग शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहे थे। रिज पर तैनात पुलिस कांस्टेबल विजेंद्र गुलेरिया ने हुड़दंग मचाने से रोका, लेकिन आरोपित पुलिस कर्मी के साथ उलझ गए। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरोपितों ने विजेंद्र को बुरी तरह पीट दिया। लोगों ने रिपोर्टिंग रूम में सूचना दे दी। कुछ ही मिनटों में अन्य पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इसके बावजूद आरोपित पुलिस कर्मी को पीटते रहे। अब तक पुलिस कर्मी लहूलुहान हो गया था। इसके बाद आरोपित मौके से भागने की कोशिश करने लगे, कुछ तो भाग भी गए, लेकिन चार को पुलिस ने पकड़ लिया। चारों का मेडिकल करवाया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है।

धुआं तो छंटा, हर माह देने पड़ रहे 800 रूपये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हर घर में रसोई गैस की सुविधा देने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ने चूल्हे के धुएं से छुटकारा तो दिला दिया लेकिन 800 रुपये हर माह सिलेंडर भरवाने के लिए खच करने पड़ते हैं। जब रसोई गैस मिली तब भी जेब से 1600 रुपये देने पड़े थे । अब पता चला है कि गैस के पैसे नहीं देने पड़े रहे हैं । पहले की अपेक्षा गैस अब ली होती तो जेब ढीली नहीं करनी पड़ती । प्रदेश के जिन घरों में रसोई गैस नहीं थी उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत यह मुहैया करवाई गई। इस योजना में प्रदेश में 96 हजार से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

छ महिलाएं इस योजना को राहत देनी वाली बताती हैं, वहीं कुछ कहती हैं कि इससे अब अतिरिक्त खर्च हो रहा है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। पहले देश में पांच करोड़ और बाद में आठ करोड़ कनेक्शन देने का प्रावधान रखा गया।

चुनावी विज्ञापनों पर सैन्य जवानों की फोटो लगाने पर रोक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का कोई भी राजनीतिक दल फायदा न उठा सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल अपने विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के साथ फोटो नहीं ले सकेंगे।

ऐसे किसी भी फोटो के साथ अपना प्रचार भी नहीं कर सकेंगे, जिनमें सैन्य जवानों की फोटो लगी हों। आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के अलावा सुरक्षाकर्मियों से संबंधित समारोह की फोटो का इस्तेमाल नहीं करना होगा ।

अगर आयोग को इससे संबंधित शिकायतें मिलती हैं तो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग को आशंका है कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल इसका फायदा ले सकते हैं। ऐसे में आयोग ने पहले ही इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है । उल्लेखनीय है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर भारतीय वायु सेना ने एयर स्ट्राइक की थी ।

पेड़ कटान पर पूर्व रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में पेड़ काटने पर लगाए पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार की दलील है कि प्रदेश में पेड़ काटने पर पूर्ण रोक लगने से बड़े प्रोजेक्टों के अलावा स्कूल, अस्पताल जैसे छोटे संस्थान बनाने में भी परेशानी आएगी।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा प्रयास करेगी कि विकास कार्यों पर ब्रेक न लगे। एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ पहले भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब एक हेक्टेयर तक की मंजूरी डीएफओ द्वारा दिए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की जाएगी।

लोकसभा चुनाव के चलते हिमाचल में वन रक्षकों की भर्ती स्थगित

HP Forest Guard Vacancy 2019 Post- 123, Circle Wise, Syllabus Exam Pattern

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के नौ वन वृत्तों में होने जा रही 123 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को विभाग ने स्थगित कर दिया है । भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का कारण लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता को बताया गया है ।

वन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वन रक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा 15 मार्च से 5 अप्रैल तक, लिखित परीक्षा 21 अप्रैल और प्रमाणपत्रों के आकलन की तिथि दो मई तय की गई थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को आगामी तिथियों की घोषणा तक स्थगित कर दिया गया है । प्रवक्ता ने कहा कि प्रवेश पत्र प्राप्त परीक्षार्थियों को परीक्षा की सूचना विभाग द्वारा पत्रों के माध्यम से भेजी जा रही है।

आचार संहिता खत्म हाते ही पौंग विस्थापितों को जमीन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सहमति नहीं दे रही है। पौंग बांध विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी।

राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान में ही 2228 मुरब्बा जमीन पौंग बांध विस्थापितों को 28 फरवरी तक आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पौंग बांध विस्थापितों को देश में आचार संहिता लगने के कारण आवंटित करने से रोकी गई है। राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद लॉटरी सिस्टम से भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा।

हिमाचल के पांच केंद्रों में होंगी इक्डोल की पीजी परीक्षाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एचपीयू के अंतरराष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र (इक्डोल) की शैक्षणिक सत्र 2018–19 के प्रथम सत्र की परीक्षाएं 25 मार्च से शुरू हो गई हैं । विवि के परीक्षा विंग ने प्रदेश में पांच परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें दो परीक्षा केंद्र विवि परिसर के आंबेडकर भवन और विधि विभाग में बनाए हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के पीजी कोर्स परीक्षार्थियों के लिए स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी, धर्मशाला और ऊना में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पांच परीक्षा केंद्रों में इक्डोल पीजी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार जारी कर दी गई है। छात्र कट लिस्ट के आधार और परीक्षा फॉर्म में भरे गए सेंटर के मुताबिक परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

परिवहन विभाग की पहल, अब कैश नहीं, क्रेडिट और डेबिट से होगी पेमेंट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

परिवहन विभाग के कार्यालय में अब वाहनों के हर तरह के शुल्कों की पेमेंट एटीएम कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होगी । परिवहन विभाग में लोगों को दलालों से छुटकारा दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। हिमाचल के क्षेत्रीय कार्यालय में यह सेवा 2 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी के पास कार्ड नहीं होगा तो व्यक्ति आरटीओ से अनुमति लेकर कैश जमा करा सकेगा।

परिवहन विभाग कार्यालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने की । राज्य परिवहन प्राधिकरण व अतिरिक्त आयुक्त सुनील शर्मा अतिरिक्त आयुक्त परिवहन हेमिस नेगी भी उपस्थित थे।

अभी तक गाड़ी की आरसी फीस, पंजीकरण शुल्क, चालान आदि की फीस कैश देकर चुकाई जाती थी। लोग यह काम दलालों से कराते थे, इसके एवज में दलाल वाहन मालिकों से कमीशन वसूल करते थे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

Padma Awards 2019: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किये

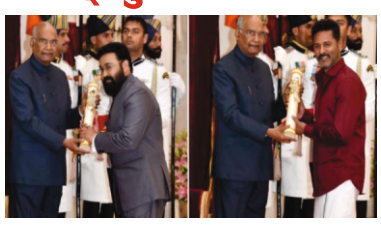

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनेता प्रभु देवा, गायक शंकर महादेवन, पहलवान बजरंग पुनिया और पत्रकार कुलदीप नैयर (मरणोपरांत) समेत 55 व्यक्तियों को 11 मार्च 2019 को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों– पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। लेखन एवं रंगमंच से जुड़े बाबासाहेब उर्फ बलवंत मोरेश्वर पुरंदर को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। हालाँकि वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सके। इसके अलावा कुलदीप नैयर (मरणोपरांत) तथा हुक्मदेव नारायण यादव समेत आठ लोगों को पद्मभूषण और 46 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

ब्रिटेन ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में 'ब्लैक होल सिक्का' जारी किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में रॉयल मिंट ने 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है। इस सिक्के को 'ब्लैक होल सिक्का' नाम दिया गया है। यह सिक्का स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च से प्रभावित है।

इस सिक्के का अनावरण स्टीफन हॉकिंग की बेटी लूसी हॉकिंग एवं बेटे टिम हॉकिंग द्वारा किया गया। रॉयल मिंट द्वारा इससे पहले, आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्का जारी हो चुका है।

प्रसन्नता रिपोर्ट में 7 स्थान नीचे फिसला भारत, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 के मुताबिक, भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में लगातार दूसरी बार फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया है जिसमें फिनलैंड लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है। प्रसन्नता रिपोर्ट सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, जीवन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उदारता जैसे संकेतकों पर तैयार की जाती है। हर साल स्थितियां विश्व स्तर पर बदल जाती हैं।

कुपोषित बच्चों का अनुपात सालाना 2 प्रतिशत की दर से घटा–रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुपोषण के वजह से कमजोर बच्चों का अनुपात वित्त वर्ष 2017–18 में करीब दो प्रतिशत कम होकर 34.70 प्रतिशत पर आ गया। इससे पहले दस वर्ष में कुपोषण में सालाना एक प्रतिशत की दर से कमी दर्ज की गयी थी।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश: SIPRI रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है। SIPRI द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट को Trend in International Arms Transfers–2018 शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में वर्ष 2014 से 2018 का अध्ययन किया गया है तथा इसी आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वर्षों के दौरान सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन कर उभरा है। जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा। लगभग 10 वर्षों तक भारत इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा था।

नासा ने चांद के इर्द–गिर्द घूम रहे जल अणुओं की खोज की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लुनर रिकॉनसाइंस ऑर्बिटर (एलआरओ) यान ने पृथ्वी से नजर आने वाले चंद्रमा के हिस्से में पानी के अणु खोजने में सफलता पाई है. हालांकि, ये अणु एक जगह पर स्थिर नहीं है। नासा जल्द ही अंतरिक्षयात्रियों को चांद पर भेजने की योजना में है, ऐसे में यह खोज काफी मददगार साबित हो सकती है। यह जानकारी जर्नल 'जियोफिजिकल रिसर्च लैटर्स' में प्रकाशित हुई है। इस खोज खोज से चांद पर पानी की पहुंच के बारे में जानने में मदद मिल सकती है जो भविष्य के चंद्र मिशनों में मानव द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारतीय नौसेना मोजांबिक के चक्रवाती तूफान इडाई में सहायता के लिए सर्वप्रथम पंहुची

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मोजांबिक में 15 मार्च को आए चक्रवाती तूफान 'इडाई' के बाद लोगों की मानवीय मदद करने और आपदा राहत प्रदान करने संबंधी मोजांबिक सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय नौसेना द्वारा अपनी पहली प्रशिक्षण स्वायड के तीन जहाजों सुजाता, सारथी और शार्दूल को मोजांबिक के पोर्ट बीरा की ओर भेजा गया। मोजांबिक के रक्षा मंत्री ने राहत कार्यो का जायजा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजो का दौरा किया। आईएनएस शार्दुल के हेलीकॉप्टर स्थानीय हवाई अड्डों से निगरानी करने और बचाव तथा राहत कार्य में कार्यरत हैं। इसके साथ ही फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए नावों, लैंडिग क्राफ्ट एसाल्ट और जैमिनी नावों की मदद ली जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र केन्या के नैरोबी में संपन्न

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र हाल ही में केन्या के नैरोबी में संपन्न हुआ. इस सत्र का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित वैश्विक समस्याओं के निदान संबंधी उपायों पर चर्चा करना था. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सत्र का विषय था–"पर्यावरण की चुनौतियों तथा सतत उत्पादन व खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान" ।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रेस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500

UN में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रद्द, चीन ने फिर लगाया वीटो

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन ने लगातार चौथी बार आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी (Global Terrorist) घोषित होने से बचा लिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो पावर (Veto Power) का इस्तेमाल कर ऐसा किया। पुलवामा हमले के बाद तीन महाशक्तियों फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ चीन ने वीटो लगा दिया। इसके साथ ही यह प्रस्ताव रद्द हो गया। पिछले दस साल में यह चौथा मौका है, जब चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाया है।

वायु प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है मधुमेह का खतरा: अध्ययन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वायु प्रदूषण के कारण मधुमेह (डायबिटीज) का खतरा भी बढ़ जाता है. यह बात चीन में हुए एक शोध से सामने आई है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वायु प्रदूषण और डायबिटीज के बीच सीधा संबंध है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

वायु प्रदूषण के कारण मधुमेह को लेकर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए 15 प्रांतों से 88 हजार डाटा लिए गए थे। इस अध्ययन में वर्ष 2004 से वर्ष 2015 की अवधि में पीएम 2.5 के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियक्त

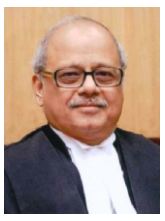

द रीव टाइम्स ब्यूरो

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के नाम को लोकपाल पद के लिए 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दी गई। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। विदित हो कि न्यायमूर्ति पी सी घोष ने ही शशिकला और अन्य को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हो गये हैं। लोकपाल की सूची में 9 ज्यूडिशियल मेंबर भी हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए खुशी जाहिर की है। यह सभी नियुक्तियां संबंधितों के पद ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी।

भारत – मालदीव ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा हाल ही में मालदीव की दो दिवसीय अधिकारिक यात्रा के दौरान तीन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। सुषमा स्वराज ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मालदीव के गृहमंत्री शेख इमरान अब्दुल्ला के साथ भी बैठक की।

सुषमा स्वराज ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भेंट की और एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लिया। वार्ता के बाद जारी साझा वक्तव्य जारी किया गया। इस वक्तव्य में मालदीव के साथ भारत के संबंधों की प्राथमिकता देने की नीति को दोहराया गया।

भारत सहित 45 देशों ने 'बोइंग 737 मैक्स 8' विमान को प्रतिबंधित किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इथोपियन एयरलाइंस के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत ने 12 मार्च 2019 को बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व के लगभग 45 देशों द्वारा भी इस तरह का कदम उठाया गया है। भारत में स्पाइस जेट के पास करीब 12 ऐसे विमान हैं, जबकि जेट एयरवेज के पास ऐसे पांच विमान हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने ट्विटर के जरिये कहा कि डीजीसीए ने बोइंग 737–मैक्स विमानों के उड़ान भरने पर फौरन प्रतिबंध लगा दिया है। ये विमान तब तक उड़ान नहीं भरेंगे, जब तक कि सुरक्षित परिचालन के लिए उपयुक्त सुधार एवं सुरक्षा उपाय नहीं कर लिए जाते।

उत्तर कन्नड़ की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में उत्पादित सिरसी सुपारी (Sirsi Supari) को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है।

चेन्नई स्थित ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री ने 04 मार्च 2019 को इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसकी जीआई संख्या 464 है। सिरसी सुपारी येलापुरा, सिद्दापुरा एवं सिरसी में उत्पादित किया जाता है। सिरसी सुपारी विशिष्ट प्रकार का उत्पाद है और यह गोलाकर तथा सिक्के की तरह सपाट है। यह विशिष्टता किसी अन्य प्रकार की सुपारी में नहीं पायी जाती।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष एहसान मनी ने 18 मार्च 2019 को दावा किया कि पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) की राशि दी है। इस मामले में भारत को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त अन्य खर्च कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित थे। पीसीबी ने साल 2018 में बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की विवाद समाधान समिति के समक्ष करीब सात करोड अमरीकी डॉलर (करीब 4 अरब 80 करोड़ 38 लाख 72 हजार 500 रुपये) के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दायर किया था।

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च 2019 को निधन हो गया. वे 63 वर्ष के थे। मनोहर पर्रिकर पिछले एक साल से अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज अमेरिका के साथ–साथ नई दिल्ली स्थित एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। मनोहर पर्रिकर के निधन से गोवा के सामाजिक राजनीतिक हालात में बहुत बड़ा असर होगा। गोवा में प्रशासनिक कार्यों पर उनकी छाप अमिट रहेगी।

श्रीसंत को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन प्रतिबंध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च 2019 को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर एस श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से श्रीसंत की सजा पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति एस श्रीसंत को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर तीन महीने के भीतर पुनः विचार कर सकती है. अदालत ने कहा कि तीन महीने में बीसीसीआई फैसला करे। अदालत ने कहा कि बीसीसीआई श्रीसंत का भी पक्ष सुने।

डीआरडीओ ने 'कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स' विकसित कीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की चिकित्सकीय प्रयोगशाला द्वारा 'कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स' विकसित की हैं। इन दवाओं से घायल जवानों को अस्पताल में पहुंचाए जाने से पहले तक के बेहद नाजुक समय को बढ़ाया जा सकेगा। डीआरडीओ द्वारा कहा गया है कि इन दवाओं का उद्देश्य पुलावामा हमले अथवा युद्ध जैसी स्थितियों में गंभीर रूप से घायलों को सही उपचार देकर जवानों की जान बचाना और मृतकों की संख्या में कमी लाना है। इन दवाओं का लाभ यह होगा कि घायल जवानों की जान बचाने के लिहाज जो महत्वपूर्ण समय होता है उसमें उन्हें जरुरी उपचार दिया जा सकता है। आमतौर पर अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही गंभीर रूप से घायल सैनिक उपचार न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं।

प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात् प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रमोद सावंत ने 18 मार्च 2019 को देर रात 2 बजे राज्यभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनियता की शपथ ली। प्रमोद सावंत को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत के साथ–साथ दो उप–मुख्यमंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदिन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण की।

कजाखस्तान के राजधानी अस्ताना का नाम बदला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कजाखस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूरसुलतान नजरबायेव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदल कर नूरसुलतान करने का सर्वसम्मति से फैसला किया। सरकारी समाचार एजेंसी 'काजिन्फॉर्म' ने संसद में मतदान की सूचना देते हुए कहा की अस्ताना का अब आधिकारिक रूप से नूरसुलतान नाम कर दिया गया है। इसकी घोषणा हाल ही में नए राष्ट्रपति कासिम–जोमात तोकायेव ने की।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

8100 करोड़ रु के बैंक लोन फ्रॉड का आरोपी हितेश पटेल अल्बानिया में गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

8100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में आरोपी आरोपी भगोड़े हितेश पटेल की अल्बानिया में गिरफ्तारी हो गई है। अल्बानिया के नेशनल क्राइम ब्यूरो ने 20 मार्च को पटेल को अरेस्ट किया। उसे जल्द भारत प्रत्यर्पण किए जाने की उम्मीद है।

पीएमएलए कोर्ट में दर्ज है मामला

पटेल के खिलाफ 11 मार्च को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वह स्टर्लिंग बायोटेक मामले में भगोड़ा है।

ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नितिन, चेतन, दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल के खिलाफ याचिका दायर की थी। चारों स्टर्लिंग बायोटेक के प्रमोटर हैं। यह गुजरात की फार्मा कंपनी है। बायोटेक का मालिक नितिन जयंतीलाल संदेसरा और उसका परिवार 8,100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड का आरोपी है। नितिन अपने परिवार समेत विदेश भाग गया। हितेश संदेसरा का रिश्तेदार है। संदेसरा परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं।

करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान के किसान मांग रहे मुआवजा

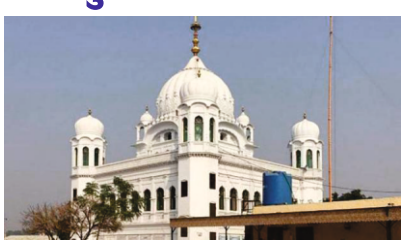

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

भारत और पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है । इसी बीच परियोजना के कारण अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर करीब 600 ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें अपनी जमीन का मुआवजा वाणिज्यिक दरों पर नहीं मिला तो वे विकास कार्य ठप कर देंगे ।

कोठे खुर्द गांव जहां की कुल आबादी करीब 600 है और जहां गुरूद्वारा डेरा साहिब करतारपुर स्थित है । वहां कि जिला प्रशासन ने गांव की पूरी आबादी को अपने मकान तत्काल खाली करने के आदेश दिए हैं ताकि करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो सके ।

हवा में प्रदूषण हर साल ले रहा है 70 लाख लोगों की जान

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण लाखों लोगों की मौत का कारण बन रहा है । वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें छह लाख बच्चे भी शामिल हैं । पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ बच्चे यानी औसतन सात में से एक बच्चा जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है । छह अरब से अधिक लोग इतनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, जिसने उनके जीवन, स्वास्थ्य और बेहतरी को खतरे में डाल दिया है । इसमें एक–तिहाई संख्या बच्चों की हैं । ये बच्चे उन इलाकों में रहते हैं जहां सामान्य के मुकाबले छह गुना या ज्यादा वायु प्रदूषण है ।

दुनिया के छह अरब से अधिक लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इसके कारण उनकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है । लोगों को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है । इस वायु प्रदूषण के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग होते है । कई वर्षों तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कैंसर, हृदय और श्वास की बीमारी से पीड़ित रहने के कारण दुनिया में हर घंटे 800 लोग अपनी जान गंवा रहे है ।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की आबोहवा में रहने की वजह से इन बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं । इसके अलावा इनके मस्तिष्क का विकास भी रुक सकता है ।

मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की 550 करोड़ रुपये बकाया चुकाने में मदद की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद दूरसंचार उपकरण कंपनी एरिक्सन का बकाया भुगतान कर दिया है। इसके फलस्वरूप रिलायंस कम्युनिकेशंस के मालिक अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल को 19 मार्च 2019 तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था अन्यथा उन्हें कोर्ट की मानहानि के मामले में जेल जाना पड़ता।

इस मामले में अनिल के साथ साथ आरकॉम की दो इकाइयों के चेयरमैन छाया विरानी और सतीश सेठ पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये और इस पर ब्याज का भुगतान कर दिया है। इससे पहले आरकॉम ने 460 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया है. आरकॉम ने इससे पहले 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

बीईई द्वारा राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज UNNATEE तैयार किया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है। UNNATEE (अनलॉकिंग नैशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशिअल) नामक रणनीति दस्तावेज ऊर्जा आपूर्ति–मांग परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए एक सादे ढांचे और कार्यान्वयन रणनीति का वर्णन करता है।

भारत की प्रभावी ऊर्जा दक्षता रणनीति का खाका विकसित करना ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और मांग पर दबाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह दस्तावेज विभिन्न विभागों, संगठनों और अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात् प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है. प्रमोद सावंत ने 18 मार्च 2019 को देर रात 2 बजे राज्यभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनियता की शपथ ली. प्रमोद सावंत को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमोद सावंत के साथ–साथ दो उप–मुख्यमंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदिन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण की।

पाकिस्तान के एक खुफिया ठिकाने में छिपा है आतंकी मसूद अजहर!

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आतंकवादी संगठन जैश का सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है । जिंदा है पर बीमार है । बीमार भी इतना कि चलना–फिरना मुश्किल है । लिहाज़ा फिलहाल बहावलपुर के करीब घोटघन्नी इलाके में एक खुफिया ठिकाने पर बिस्तर पर पड़ा है, और उसकी हिफाजत के लिए उसके अपने कमांडर के साथ–साथ पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस कमांडो भी चौबीसों घंटे मसूद अजहर की हिफाजत में लगे हैं । उसे इजाजत नहीं है कि वो अपने ही लोगों से मिले या फिर किसी तरह का कोई बयान जारी करे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ले ।

चक्रवात के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 हो सकती है: जिम्बाब्वे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

उष्णकटिबंधीय चक्रवात इडाई की वजह से जिम्बाब्वे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई है और यह संख्या बढ़कर 300 तक पहुंच सकती है । वहां के मंत्री जुलाई मोयो ने संवाददाताओं को कैबिनेट की एक बैठक के बाद बताया कि मृतक संख्या इस समय करीब 100 है ।

मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्ते बेहतर हुए: ट्रम्प प्रशासन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मोदी सरकार में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं । ट्रम्प प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के बाद संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली में पिछले साल सितंबर में दोनों देशों के बीच हुई 22 वार्ता से रिश्तों को आगे ले जाने में काफी मददगार रही।

मसूद को बचाने के पीछे है चीन की बड़ी चाल, PAK प्रेम दिखाकर साध रहा कई निशाने

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन ने आखिरकार अपना रंग दिखा दिया । लगातार चौथी बार चीन जैश सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने में रोड़ा बन गया । 'ड्रैगन' का 'मसूद प्रेम' यूं ही नहीं है । दरअसल, इसके पीछे चीन के ऐसे कई हित हैं जो मसूद अजहर का बचाव करने से साधे जा रहे हैं ।

कूटनीतिक संबंधों में जोखिम नहीं लेना चाहता चीन कूटनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे के सहयोग में तब तक खड़ा नहीं होता जब तक कि उसमें उसके राष्ट्रीय हित शामिल न हों । चीन जैसा देश तो बिना बड़ी वजह के ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेता ।

पुलवामा के बाद तैयार थी नेवी, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए परमाणु पनडुब्बी की तैनाती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत–पाकिस्तान के बीच तनाव इस कदर बढ़ने लगा मानो जंग की नौबत आ गई । इस दौरान जहां थल सेना ने जम्मू–कश्मीर में बॉर्डर और स्वब पर पाक की हिमाकत का सख्त जवाब दिया, वहीं एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया ।

इस दौरान इंडियन नेवी भी पूरी तरह तैयार थी । नौसेना ने समंदर में पाकिस्तान की किसी भी हरकत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने सारे अस्त्र–शस्त्र को तैयार कर रखा था । बस दुश्मन की ओर से एक चूक भर की देर थी और फिर उसे ऐसा सबक सिखाया जाता जो इतिहास बनने वाला था । भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अहम ठिकानों पर परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती भी कर दी थी ।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष एहसान मनी ने 18 मार्च 2019 को दावा किया कि पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) की राशि दी है।

इस मामले में भारत को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त अन्य खर्च कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित थे. पीसीबी ने साल 2018 में बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की विवाद समाधान समिति के समक्ष करीब सात करोड अमरीकी डॉलर (करीब 4 अरब 80 करोड़ 38 लाख 72 हजार 500 रुपये) के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दायर किया था।

भारत ने 17 अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास शुरु किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत और अफ्रीकी देशों हेतु अफ्रीका–भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास –2019 (एएफआईएनडीईएक्स–19) का उद्घाटन समारोह 18 मार्च 2019 को औंध मिलिट्री स्टेशन, पुणे में आयोजित हुआ। यह अभ्यास कार्यक्रम 18 मार्च से 27 मार्च 2019 तक चलेगा. भारतीय सेना ने 17 अफ्रीकी देशों के साथ दस दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की जो भारत एवं अफ्रीकी महाद्वीप के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों को दर्शाता है।

मेजर जनरल संजीव शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, गोल्डन कटार डिवीजन, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे. उद्घाटन समारोह में चीता हेलिकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरों ने संयुक्त राष्ट्र, भारत और एएफआईएनडीईएक्स–19 के झंडे लहराए. मुख्य अतिथि और अफ्रीकी देशों के रक्षा अधिकारियों ने परेड की समाप्ति के बाद प्रतियोगियों के साथ बातचीत की।

नीरव मोदी की जमानत अर्जी खारिज, जेल में रहेगा भगोड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ऐसे में नीरव को कुछ और समय लंदन की जेल में ही रहना होगा। लंदन की कोर्ट ने इसे असामान्य धोखाधड़ी केस कहा। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारतीय प्राधिकरण की तरफ से पेश हुए क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के टॉबी कैडमैन ने लंदन की अदालत को बताया कि नीरव मोदी ने एक गवाह आशीष लाड को बुलाकर, उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। कैडमैन ने कोर्ट में यह भी कहा कि नीरव मोदी भारतीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट में नीरव की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि नीरव मोदी को कोर्ट से जमानत न दी जाए। वह जमानत मिलने पर देश छोड़ने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वह सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकता है।

इराक में नाव पलटने से 19 बच्चों समेत 94 की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इराक के मोसुल में दजला (टिग्रिस) नदी में नाव पलटने से 94 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।

हादसे के बाद प्रधानमंत्री अदेल अब्देल महदी ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने 11 मार्च 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में जितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया– चार
- जिस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की 'फॉर्मोसन क्लाउडेड' प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई है– ताइवान
- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर जितने प्रतिशत करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है–27 प्रतिशत
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018–19 और वर्ष 2019–20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर जितने फीसदी की ब्याज सहायता (सब्सिडी) के संदर्भ में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया– दो फीसदी
- केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले जितने गैर–अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87 प्रतिशत तक कमी कर दी है–390
- वह स्थान जहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स–2019 में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है–बर्लिन
- वह गाइडेड रॉकेट प्रणाली जिसका भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है – पिनाक
- वह देश जिसने 2014–18 के दौरान सबसे अधिक हथियार आयात किये हैं – सऊदी अरब
- कला क्षेत्र से जुड़ी इन शख्सियत को हाल ही में पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया –तीजन बाई
- बांध पुनर्वासऔर सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए इतनी सहायता राशि देने की घोषणा की है – 137 मिलियन डॉलर
- वह विमान जिसे भारत सहित 45 देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है – बोइंग 737 मैक्स 8
- इन्हें हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है – सी. लालसावता
- वह संगठन जिसने हाल ही में युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की है – DRDO
- वह राज्य जहां हाल ही में मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना शुरू की गई है –उत्तराखंड
- वह आईआईटी संस्थान जिसके लिए SPARC योजना के तहत सात अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है – आईआईटी मंडी
- जिस देश में 11 साल में करीब 88,000 लोगों पर हुए अध्ययन में सामने आया है कि वायु प्रदूषण में ज्यादा देर तक रहने के कारण इंसानों में डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है– चीन
- जिस आईआईटी के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया है– आईआईटी खड़गपुर
- चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक, चीन और जिस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF–17 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है– पाकिस्तान
- ऐक्सिस बैंक ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एसकेएफ की भारतीय यूनिट के चेयरमैन राकेश मखीजा को जितने साल के लिए गैर–कार्यकारी पार्ट टाइम चौयरमैन बनाया है– तीन साल
- पुरातत्वविदों ने हाल ही में जिस राज्य में करीब 5,000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं– गुजरात
- भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को इस नाम से आयोजित किया गया है –अल नागाह–III
- दक्षिण भारत का वह स्थान जहां की हलदी को जीआई टैग हासिल हुआ है –इरोड
- जीव विज्ञानियों द्वारा इंडोनेशिया के एक द्वीप में खोजी गई बीटल्स (Beetle) की प्रजातियों की संख्या –103
- भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा केरल के दक्षिणी–पश्चिमी घाट में इस जीव की नई प्रजाति की खोज की गई – मेंढक
- वह देश जिसने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में 'ब्लैक होल कॉइन' जारी किया है – ब्रिटेन
- भारत और जिस देश ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों ने सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है– अमेरिका
- वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अपनी 200वीं वनडे पारी में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं– रोहित शर्मा
- एचडीएफसी बैंक 13 मार्च 2019 को जितने लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई–6 लाख करोड़ रुपये
- जिस देश की सरकार ने वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कई बिल पास किए हैं जिनमें प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर स्वीकारा गया है– दक्षिण कोरियाई
- वह देश जिसने एक बार फिर आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया है– चीन
- सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल स्पॉट–फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई द्वारा जिस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है– श्रीसंत
- कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की जिस पहली महिला जगदगुरु और बसवा धर्म पीठ प्रमुख का 14 मार्च 2019 को बेंगलुरु के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया– माते महादेवी
- कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, एम.आर. कुमार को जितने साल के लिए देश की सबसे बड़ी व सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है–5 साल
- भारत ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान से मांग की है कि वह ऐतिहासिक करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने के लिए प्रतिदिन जितने भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालुओं को वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दे–5,000 भारतीय
- आईपीएल 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने जिस पूर्व भारतीय कप्तान को टीम के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है– सौरव गांगुली
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इस नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है –GEO–6
- इन दिन विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है – 15 मार्च
- वह देश जहां एक आतंकी ने दो मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है –न्यूजीलैंड
- वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक घोषित किया है – आईडीबीआई
- वह राज्य जहां वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है – केरल
- चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 इतने चरणों में कराये जायेंगे –सात
- वह राज्य जिसके राज्यपाल द्वारा हाल ही में ओबीसी को 27: आरक्षण दिया गया है – मध्य प्रदेश
- वह देश जहां वैज्ञानिकों के एक दल ने ओर्का व्हेल की प्रजाति का पता लगाया है जो दुर्लभ किलर व्हेल की नई प्रजाति हो सकती है – चिली
- चुनाव आयोग द्वारा अभिनेता–नेता कमल हासन की मक्कल नीति मय्यम (एमएनएम) पार्टी को दिया गया चुनाव चिन्ह है – टॉर्च
- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर की गई सूरत मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत है – 12,000 करोड़ रुपये
- वह जापानी महिला जिसे 116वर्ष की आयु में विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है –काने तकाना
- राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा हाल ही में 390 गैर–अनुसूचित कैंसर दवाओं के दाम में की गई कमी का प्रतिशत है – 87:
- इन्हें हाल ही में फिलिस्तीन के नये प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया – मोहम्मद शतयेह
- भारत का वह स्थान जहां मिलने वाले मरयूर गुड़ को हाल ही में जीआई टैग मिला है –इडुक्की
- चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में लोकसभा की इतनी सीटों के लिए सात चरणों में अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराये जायेंगे –543
- जिम्बाब्वे में हाल ही में इस नाम से आये चक्रवात से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है –इडाई
- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 के ग्लोबल कॉस्ट आफ लिविंग सर्वेक्षण के मुताबिक यह शहर रहने के लिहाज से विश्व में सबसे महंगा है–पेरिस
- जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में किफायती मकानों पर इतने प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने का अनुमोदन किया गया है –1 प्रतिशत
- इन्हें हाल ही में देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है –पिनाकी चंद्र घोष
- यूनेस्को द्वारा विश्व में पानी की स्थिति के बारे में जारी की गई वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक है – Leaving No One Behind
- भारत और जिस देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जायेगा– श्रीलंका

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों मे कितने नए मतदाता प्रथम बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे–88, 127
- हिमाचल से संबंध रखने वाले पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया– डा. जगतराम तोमर, इनके नाम नेत्र विशेषज्ञ के रूप में 10 हजार बच्चों और एक लाख से अधिक लोगों के ऑपरेशन किए हैं।
- 19 मई को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनावों के लिए कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं–7723
- हिमाचल के किस जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का ट्राइबल फेस्टीवल होने जा रहा है– जिला बिलासपुर
- हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है– मंडी
- हिमाचल से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया– बुद्धि सिंह, कोटधार
- नेहरूकुंड और सोलंगनाला पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है– मनाली, जिला कुल्लू
- प्रदेश में सबसे अधिक मतदान केंद्र किस लोकसभा क्षेत्र में है– मंडी(2079)
- मंडी में कितने नए मतदान केंद्र बनाए गए– 94
- प्रदेश में सबसे कम लोकसभा मतदान केंद्र किस जिले में है–हमीरपुर(1764)
- सर्वेक्षण 2019 के अनुसार स्वच्छता के मामले में हिमाचल की कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही है– बद्दी नगर परिषद, जिला सोलन
- प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदात किस जिले में है– कांगड़ा
- प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों में सबसे कम मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है– शिमला
- सबसे पहले लोकसभा चुनावों में किन्नौर में किस तारीख को चुनाव आयोजित किए गए थे– 23 अक्तूबर 1951
- हिमालयन ट्राउट फिश फार्म की स्थापना कब हुई –कुल्लू मनाली वामतट मार्ग पर 1992 में हुई थी।
- चितरोड़ी त्योहार कहां पर मनाया जाता है– लाहौली घाटी में जब घाटी के लोगों को बर्फबारी से राहत मिलती है तो सुख समृद्धि की कामना के लिए इस त्योहार का आयोजन किया जाता है।
- प्रदेश के किस जिले में 100 से अधिक आयु के सबसे मतदाता है–कांगड़ा
- प्रकाश बादल कौन है– हिमाचल के प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर
- हिमाचल में 2014 के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था–65.18 प्रतिशत
- वर्ष 2014 के चुनावों किस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था–हमीरपुर–67.88 प्रतिशत
- प्रदेश में 2 नए इंडस्ट्रियल पार्क कहां बनेंगे– कांगड़ा के परागपुर के चन्नौर व नूरपुर मे
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन के अंतगर्त हिमाचल प्रदेश में कितने कलस्टर चयनित किए गए हैं–6
- मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना के तहत कितने प्रतिशत योगदान दिया जाता है– 85 प्रतिशत
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कितने प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है– 50 प्रतिशत
- मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग और बल्ह घाटी के देवता सत देव बाला कामेश्वर के बीच क्या संबंध है– पिता –पुत्र का
- हिमाचल प्रदेश में वनों को आग से बचाने के लिए कौन सा नया सिस्टम शुरू किया गया है– सेटेलाइट अलर्ट सिस्टम
- हिमाचल के किस संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना गया है– डाक्टर वाईएस परमार नौणी के पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केंद्र को

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही दो महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि योजनाओं के लिए क्या पात्रता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी बेटी के विवाह की लागत का खर्च नहीं उठा सकते हैं। पहले इस योजना के तहत 25,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है।

ये हैं पात्र

अनाथ लड़कियों, नारी निकेतन, बालिका आश्रम में रहने वाली लड़कियों, तलाकशुदा और तलाकशुदा दंपति की लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। नियमों के तहत कन्यादान राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित लड़कियां पंचायत, स्थानीय निकाय, बाल कल्याण परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, नारी सेवा सदन, नारी निकेतन और अधीक्षक बाल आश्रम के पास आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र की जिला परियोजना अधिकारी से पुष्टि की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन में जन्मतिथि का सुबूत, जिस लड़के से शादी हो रही है, उसका पूरा ब्योरा, शादी की तारीख की स्थानीय स्तर से पुष्टि, आय के प्रमाणपत्र भी देने होंगे। सभी आवेदनों की पूरी जांच होने के बाद जिला परियोजना अधिकारी की ओर से कन्यादान राशि जारी की जाएगी।

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के लाभ

- यह योजना पात्र लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत 40,000 रूपये की वित्तीय सहायता लाभार्थी लड़कियों को उनकी शादी के लिए प्रदान की जाती है।

आवश्यक पात्रता और शर्तें

- योजना हिमाचल प्रदेश की निवासी लड़कियों के लिए है।
- लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनका पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम या अस्पष्ट है, योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

गूगल पर एचपी वूमैन एंड चाइल्ड वैल्फेयर डिपार्टमेंट का लिंक डालते ही विभाग की योजना जान सकते हैं।

यहां पर डाउनलोड लिंक पर जाकर योजना फार्म डाउनलोड किया जा सकता है।

इस योजना के लिए आप हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं महिला कल्याण विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं।

योजना का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी जानकारी ले सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आप जिला कार्यालय के पास संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश मे विधवा पुनर्विवाह योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी विधवा पुनः–विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुनः–विवाह में मदद करना और विधवाओं के साथ पुनर्विवाह करने के लिए पुरुषो को प्रोत्साहित करना है। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 50, 000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 20,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 30,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है। पहले इस योजना के तहत भी 25 हजार देने का ही प्रावधान था लेकिन बाद में योजना नियमों संशोधन कर राशि को दोगुना कर दिया गया।

इस पहल ने राज्य के कई असहाय विधवाओं की मदद की है। हिमाचल की सभी विधवा स्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक विवरण और आवेदन फार्म निकटतम जिला कल्याण कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, में प्राप्त किया जा सकता है।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ

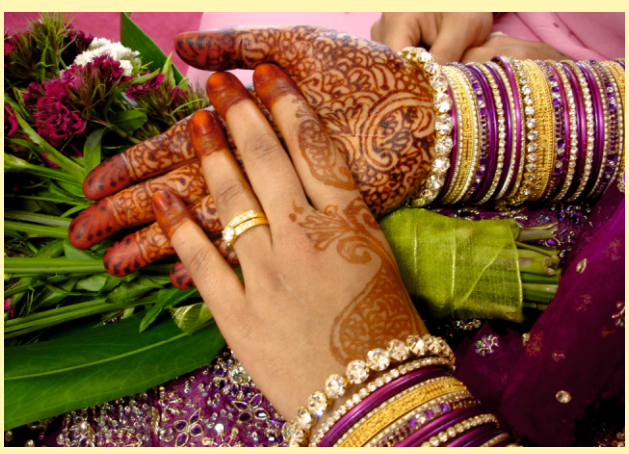

यह योजना पात्र विधवा को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 25,000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 10,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 15,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन विवाह करने के छह माह के भीतर करना अनिवार्य है। इसके लिए योग्यता की पुष्टि करनी भी जरूरी है और जिला या तहसिल कल्याण कार्यालय में आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र उसी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

- http://himachal.nic.in/index1.php?

आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी ही कार्यालय में जमा करें। आवेदन उनकी शादी के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

आवश्यक पात्रता और शर्तें

महिला और पुरुष दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए ।

पुरूष की उम्र 21 से कम न हो
महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम न हो
आवश्यक दस्तावेज
पासपोर्ट आकार का फोटो
बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
पहचान प्रमाण
पुरुष और महिला दोनों के निवासी प्रमाण
आधार कार्ड
विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति का नाम और पता
फिर से पुनर्विवाह की तिथि
पहली शादी की तिथि
वह तिथि जब वह विधवा हो गई

मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा महिलाओं, विधवाओं को अधिकतम 2 बच्चों तक उनके पालन–पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। सरकार ने इसके लिए पात्रता और नियम तय किए हैं।

पात्रता

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की निःसहाय महिलांए

विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं,

महिलाएं जिनके पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में उनके न मिलने की रिपोर्ट दर्ज हों, या

इस श्रेणी की महिलाएं यदि गरीबी रेखा से नीचे न हों तो परिवार की वार्षिक 35000 रूपये तक होना अनिवार्य है

जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों

सहायता राशि

दो बच्चों तक प्रति वर्ष 3000 रूपये प्रति बच्चा 18 वर्ष तक की आयु तक।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करें:

आय का प्रमाण पत्र,

पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र,

हिमाचली प्रमाण पत्र,

परिवार रजिस्टर की नकल,

आधार कार्ड की छायाप्रति,

ग्राम सभा का प्रस्ताव,

आवेदन पत्र, फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

कृषोन्नति योजना हरित क्रांति

किसानों के विकास के लिये शुरु की गई महत्वकांक्षी योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

सरकार ने देश में चल रही 'हरित क्रांति–कृषोन्नति योजना' की समय सीमा को और बढ़ा दिया है और अब ये योजना साल 2020 तक हमारे देश में जारी रहेगी । छतरी योजना यानी 'अम्ब्रेला स्कीम' 'हरित क्रांति–कृषोन्नति योजना' के अंदर ग्यारह योजनाओं को शामिल किया गया है और ये सभी योजनाएं हमारे देश के किसानों के विकास और उनकी इनकम में वृद्धि से जुड़ी हुई हैं ।

ऐसे समझें

योजना का नाम छतरी योजना 'हरित क्रांति–कृषोन्नति योजना'
किसके द्वारा चलाई गई ये योजना : केन्द्र सरकार
योजना के अंतर्गत आने वाली कुल योजनाएं : 11
योजना की अवधि : साल 2020 तक
किस क्षेत्र से जुड़ी है ये योजना :
कृषि क्षेत्र योजना का बजट : 33,26 9.9 76 करोड़
छतरी योजना 'हरित क्रांति–कृषोन्नति योजना' के लक्ष्य
छतरी योजना– 'हरित क्रांति–कृषोन्नति योजना' की मदद से सरकार किसानों की हर संभव मदद करना चाहती है ताकि किसान फसलों का उत्पादन अच्छे से कर सकें और इनकी इनकम में बढ़ोतरी हो सके ।
इन योजना की मदद से सरकार कृषि क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने चाहती है ।
ये सभी योजनाएं (11 योजनाएं) कृषि क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं जैसे कि कपास की खेती में होने वाली परेशानी और पौधों में कीड़े लगने सहित अन्य समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगी । क्योंकि किसानों की समस्याओं के हल होने से उनकी फसलों का उत्पादन और बढ़ सकेगा, जिससे की किसानों को बेहतर लाभ मिलना सुनिश्चत हो सकेगा ।

योजना का बजट

इन सभी स्कीमों (11 योजनाओं) को जारी रखने के लिए सरकार को तीन वित्तीय वर्षों के लिए 33,26 9.9 76 करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि साल 2017–18 से लेकर साल 2019–20 तक के लिए होगा।

छतरी योजना के अंतर्गत आने वाली सभी 11 योजनाओं की जानकारी

नीचे बताई गई सभी योजनाओं को पहले सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जा रहा था लेकिन साल 2017–18 में, इन सभी योजनाओं को क्लब करने का फैसला लिया गया है । जिसके बाद से ये सब योजनाएं छतरी योजना– 'हरित क्रांति–कृषोन्नति योजना' के तहत जानी जाएंगी ।

1.बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन

योजना का लक्ष्य– बागवानी क्षेत्र से जुड़ी इस योजना का लक्ष्य इस क्षेत्र का विकास करने के साथ–साथ बागबानी उत्पादन को बढ़ावा देना है, किसानों को बागबानी क्षेत्र से जोड़ना है और उनको आय समर्थन देना है ।
योजना का बजट– कुल 33,26 9.9 76 करोड़ रुपए के बजट में से सरकार इस योजना पर 7533.04 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
2.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तेल बीज और तेल पाम राष्ट्रीय मिशन (एनएमओयूपी)

योजना का लक्ष्य–

इस योजना की मदद से सरकार हमारे देश में चावल, गेहूं, दाल, अनाज और अन्य तरह की फसलों के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है और अपना ये लक्ष्य सरकार उपयुक्त तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से करेगी ।
इसके अलावा सरकार इस योजना की मदद से देश में तेल के बीजों की खेती में वृद्धि करना चाहती है ताकि हमारे देश को अन्य देशों से तेल का आयात नहीं करवाना पड़े ।
योजना का बजट – इस योजना को सही तरह से चलाने के लिए सरकार ने 6893.38 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए निर्धारित किया है ।

स्थिर कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)

योजना का लक्ष्य–
स्थिर कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य उपयुक्त मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी और टिकाऊ कृषि तकनीक की मदद से स्थिर कृषि को हमारे देश में बढ़ावा देना है ।
योजना का बजट – इस योजना के लिए सरकार 33,269.976 करोड़ रुपए में से 3980.82 करोड़ रुपये आवंटित करेंगी ।

कृषि विस्तार के लिए उप मिशन (एसएमएई)

योजना का लक्ष्य–
इस योजना का लक्ष्य खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करना, किसानों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करना, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की व्यवस्था को और मजबूत करना, स्टेकहोल्डर्स के बीच संपर्क कायम करना, मानव संसाधन विकास को समर्थन देना और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आईसीटी उपकरण को इनॉवेटिव बनाना है ।
योजना का बजट – इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार को 2961.26 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा ।

5. बीज और रोपण सामग्री के लिए उप–मिशन (एसएमएसपी)

योजना का लक्ष्य–
इस योजना की मदद से सरकार निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है ।
इस योजना की सहायता से सरकार सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड के उत्पाद को देश में बढ़ाना चाहती है और खेती करने के लिए बचाए गए बीजों की क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहती है ।
बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, परीक्षण जैसी चीजों से जुड़ी नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों (technologies and methodologies) को बढ़ावा देना ।
बीज उत्पादन, भंडारण, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी आदि के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और सही करना चाहती है ।
योजना का बजट– बीज और रोपण सामग्री के लिए उप–मिशन (एसएमएसपी) योजना के लिए सरकार ने 920.6 करोड़ रुपए का बजट तय किया है ।

6.कृषि मशीनीकरण के लिए उप मिशन

योजना का लक्ष्य
इस योजना का उद्देश्य छोटे और मार्जिनल किसानों तक फार्म मशीनीकरण – को पहुंचाना है ताकि इसके इस्तेमाल से कृषि कार्यकर्ता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके । इसके अलावा फार्म मशीनीकरण को उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाना है जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है ।
इस योजना से सरकार व्यक्तिगत स्वामित्व (Individual Ownership) की उच्च लागत में कमी लाने के लिए कस्टम भर्ती केंद्रों का प्रचार और हाई–टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्रों का निर्माण करेगी और स्टेकहोल्डर्स के बीच अवेयरनेस पैदा करने के लिए विभिन्न नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करेगी ।
योजना का बजट– केंद्रीय सरकार कृषि मशीनीकरण के लिए उप मिशन (एसएमएएम) पर 3250 करोड़ रुपए खर्च करेगी ।

7.पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन

योजना का लक्ष्य–
इस योजना की मदद से सरकार फसलों पर कीड़े और अन्य कीटाणु लग जाने से होने वाले नुकसानों को कम करना चाहती है और इन कीड़े और अनचाहे पौधों, की वजह से फसलों की गुणवत्ता को भी होने वाले नुकसान को खत्म करना चाहती है ताकि फसलों की पैदावार अधिक हो सके ।
इस योजना का अगला लक्ष्य पौधों की सुरक्षा रणनीतियों के संबंध में विशेष रूप से अच्छे कृषि तकनीक को बढ़ावा देना है । ताकि किसान अपनी फसल को कीड़ों से बचा सके ।
इस योजना की मदद से सरकार वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात को सुविधा जनक बनाना चाहती है ताकि कृषि वस्तुओं का आसानी से निर्यात किया जा सके ।
योजना का बजट– पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव के उपमिशन (एसएमपीपीक्यू) के लिए सरकार ने 1022.67 करोड़ रुपए का बजट तय किया है ।

8.कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना

योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य कृषि जनगणना और प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करना है और देश की कृषि–आर्थिक समस्याओं पर शोध, फसल को बोने से लेकर उनको काटने तक की पदानुक्रमित सूचना प्रणाली (hierarchical information system) और कृषि स्टेटिस्टिक्स कार्यप्रणाली में सुधार करना भी है।
इस योजना के तहत अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले सम्मेलनों, सेमिनार, और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए फंड देना भी है ।
योजना का बजट –कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना के लिए कुल 33,26 9.9 76 करोड़ रुपए में से 730. 58 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है ।

9.कृषि सहयोग के लिए एकीकृत योजना

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य वित्तीय सहायता की मदद से कोऑपरेटिव की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना है ।
कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण में सहकारी विकास में तेजी लाना है । कपास किसानों को उनके कपास के लिए सही मूल्य दिलवाना है और डेंटरलिज्ड वीवर्स को भी सही मुल्यों पर गुणवत्ता संपन्न रूई की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
योजना का बजट – कृषि सहयोग के लिए एकीकृत योजना के लिए केंद्रीय सरकार ने 1902.636 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है ।

10 कृषि विपणन पर एकीकृत योजना

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव और नई प्रौद्योगिकी और विकल्पों को बढ़ावा देना है । ग्रेडिंग, स्टैंडर्डजेशन और कृषि उपज के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा प्रदान करवाना है ।
इस योजना का जो अगला लक्ष्य है वो राष्ट्रस्तर पर मार्केटिंग सूचना नेटवर्क को स्थाइत्व प्रदान करना है और बाजार को एकीकृत करने के लिए ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा देना है ।
योजना का बजट – एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इस योजना पर सरकार का कुल खर्चा 3863.93 करोड़ रुपए का आएगा ।

11 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस (एनईजीपी–ए)

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य कई तरह के कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों के लिए केन्द्रीयता और सेवा अभिविन्यास (centricity & service orientation) को लाना है.
विस्तार सेवाओं की पहुंच और प्रभाव, किसानों की सेवाओं में सुधार, केंद्र और राज्यों की मौजूदा आईसीटी पहल को बढ़ाना और एकीकृत करना है । इसके अलावा समय समय पर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाना भी है ।
योजना का बजट– राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस (एनईजीपी–ए) मिशन के लिए सरकार ने कुल 211.06 करोड़ रुपए का बजट तय किया है और ये बजट साल 2020 तक के लिए है ।
मोदी गवर्नमेंट ने किसानों के विकास और उनकी इनकम को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने किसानों से जुड़ी (यहां बताई गई) सभी योजनाओं की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है । ताकि सरकार जल्द से जल्द किसानों का विकास कर सके और उनकी मदद इन स्कीम के जरिए कर सके ।

MISSION RIEV

MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages

CERTIFIED NSDC TRAINING

रोजगार का सुनहरा अवसर

सर्विस एसोसिएट के पदों को भरने कि लिए प्रशिक्षण

प्रशिक्षण हेतु NSDC द्वारा विद्या कौशल लोन सुविधा
इसमें शामिल होगा (तकनीकि शुल्क –8000/–, टैबलेट 12000/–
3 दिन का संस्थागत प्रशिक्षण–5000/–)

आवेदन करें
www.missionriev.in
www.recruitment.missionriev.in

प्रथम बैच 15 अप्रैल से आरम्भ

योग्यता 12वीं पास या समकक्ष

200 घन्टें का NSDC मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण

1 मई से नियुक्ति, मासिक आय 10,000 हजार से 18,000

LAST DATE 12 April 2019

For Detail : 01772843528/2844073, 9816741687, 7876052696, 82196 94079, 7018537413 T&C Apply*

MISSION RIEV SECRETARIAT, IIRD COMPLEX, BY PASS ROAD, SHANAN, SHIMLA-6, HIMACHAL PRADESH

पृथ्वी से जुड़ी कुछ अनसुने रहस्य जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा

1. आकाश–गंगा की एक परिक्रमा को पूरी करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। 25 करोड़ साल की इस लम्बी अवधि को ब्रह्माण्ड–वर्ष या कॉस्मिक–इयर (Cosmic & Year) के नाम से जाना जाता है।
2. हमारा सौरमंडल को मन्दाकिनी (Milky Way) का चक्कर लगाने में करीब 225 मिलियन साल लगते है।
3. यदि आप एक ब्लैक होल में होते और अंदर से बाहर देखते, तो आकाश के एक छोटे पैच में पूरे ब्रह्मांड को देखने के साथ–साथ अपने सर का पिछला हिस्सा भी देख पाते।
4. अगर आप ब्रह्मांड में कही से भी सफर शूरू करेंगे और सीधा जाएंगे तो आप वापस उसी जगह पर आ जाएंगे लेकिन आपको ब्रह्मांड का कोई दूसरा छोर नहीं मिलेंगा ।
5. हमारी पृथ्वी से 33 प्रकाश वर्ष दूर एक exoplanet है जो पूरी तरह से जलती हुई बर्फ से ढका हुआ है।
6. हमारी आकाशगंगा के केंद्र में बदबू रम की तरह आती है।
7. हमारे सौरमंडल का सबसे ऊँचा पहाड़ मंगल गृह पर है जिसके सामने एवेरेस्ट की चोटी बहुत छोटी है।
8. पृथ्वी की गति हर 100 वर्षो में घटते जा रही है। करीब 17 मिलिसेकंद – 100 वर्ष ।
9. अंतरिक्ष में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं है ।
10. काला पदार्थ (Dark Matter) वह गोंद है जो ब्रह्मांड को जोड़े रखता है और जिसे मापा नहीं जा सकता।
11. Dinosaur के युग में 22 घंटे का दिन हुआ करता था ।
12. ब्रम्हाण्ड में हर रोज करीब 275 मिलियन तारे जन्म लेते है।
13. ब्रह्माण्ड में सूर्य से भी कई गुना बड़े कई तारे है ।
14. पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल बादल है जो अनगिनत शराब से भरा है।
15. हमारा 90 प्रतिशत शरीर तारो के तत्वों (stardust) से बना है।

इजराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई

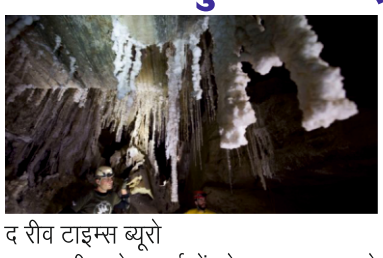

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इजराइली खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नजदीक विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज निकाली है। येरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय ने 28 मार्च 2019 को यह जानकारी दी। इजराइल के माउंट सोडोम से होकर जाती हुई इस गुफा की लंबाई 10 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पहले ईरान में विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा होने का रिकॉर्ड था। माउंट सोडोम इजराइल का सबसे लंबा पहाड़ है। इस गुफा का नाम माल्हम रखा गया है जो मृत सागर के दक्षिण पश्चिम कोने तक फैली है। इस गुफा की छत से लटके नमक के टुकड़े धातु की तरह चमकते हैं। इनसे बूंद–बूंद कर खारा पानी भी रिसता रहता है।

चंद्रयान–2 नासा के लेजर उपकरणों को चंद्रमा तक लेकर जाएगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चंद्रयान–2 से पहले इजरायल के बेरशीट लैंडर के साथ भी नासा का लेजर रेट्रोरिफलेक्टर भेजा गया है। बेरशीट 11 अप्रैल को चांद पर उतर सकता है। चंद्रयान–दो (Chandrayaan–2) नासा के लेजर उपकरणों को अपने साथ चंद्रमा तक लेकर जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा तक की दूरी का सटीक माप लेने में मदद मिलेगी। चंद्रयान–2 से पहले इजरायल के बेरशीट लैंडर के साथ भी नासा का लेजर रेट्रोरिफलेक्टर भेजा गया है। बेरशीट 11 अप्रैल को चांद पर उतर सकता है। चंद्रयान–2 भारत का चंद्रयान–1 के बाद दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है। इस अभियान को श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा भेजे जाने की योजना है. उड़ान के समय इसका वजन लगभग 3,250 किलो होगा।

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स उत्कृष्ट गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रूपये, छः माह के लिए 250/रूपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़